हिन्दी, उर्दू, पंजाबी में एक साथ प्रकाशित दिल्ली सरकार की मासिक पत्रिका

अंकः अप्रैल–जून 2015

दिल्ली

ਦਿੱਲੀ دلّی

केवल 4 महीने में हमने दिल्ली में–

- भ्रष्टाचार खूब कम कर दिया।
- बिजली बिल आधे कर दिये।
- आपका पानी मुफ्त कर दिया।
- पावर कट बहुत कम हो गये।
- पानी की किल्लत बहुत कम हो गई।
- 1260 कि.मी. PWD की सड़कों के सारे गढ्ढे भर दिये।

जो कहा सो किया

– अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार

अब दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बंद होगी

''अब हम शिक्षा के नाम पर दिल्ली में चल रहे माफिया के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं। हर घर में माता–पिता अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर परेशान है। दिल्ली में कई प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं। लेकिन कुछ स्कूलों ने लूट मचा रखी है। एडमिशन में धांधली करते हैं, मनमानी फीस लेते हैं। गरीब बच्चों के दाखिले के नाम पर धोखा धड़ी हो रही है। हमें इस लूट को बंद करना है। अब हम कानून लाने जा रहे हैं। जो स्कूल गलत काम करें उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। इसमें हमें आपका साथ और आपके सुझाव चाहिए।''

– मनीष सिसोदिया
उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री
दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार
दिल्ली टीम–स्वप्न करे साकार

शिक्षा विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

DELHI GOVERNMENT
Team Delhi, Making things happen

हम सब भारतवासी मिलकर देश को बदलेंगे

दिल्ली

अंक : अप्रैल–जून 2015

प्रधान सम्पादक
सज्जन सिंह यादव

अतिरिक्त निदेशक
राजेश चोपड़ा

सम्पादक
नलिन चौहान

सम्पादकीय सहयोग
कंचन आजाद, विनोद गुप्ता
चन्दन कुमार, अमित कुमार
मनीष कुमार, उर्मिला बेनिवाल

छाया चित्र
सुधीर कुमार, अजय कुमार, योगेश जोशी

"दिल्ली" पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार रचनाकारों के अपने हैं तथा दिल्ली सरकार का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं।

पत्राचार का पता
प्रधान सम्पादक
दिल्ली सूचना एवं प्रसार निदेशालय
दिल्ली सरकार
खंड सं. 9, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054
दूरभाष : 23819046, 23817926
फैक्स : 23814081
ई–मेल : delhidip@gmail.com

इस अंक में...

हिन्दी

परिवहन विभाग ने आयोजित किया ऑटो संवाद 10
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शुरू की भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन 12
जापानी प्रतिनिधिमंडल के छह सदस्यों ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात 14
दिल्ली जलबोर्ड ने एसएमएस सुविधा 15
केजरीवाल सरकार की विभिन्न कार्य झलकियां 16
दिल्ली जलबोर्ड की बड़ी राहत 18
दिल्ली को अगले पांच साल में दुनिया के मानचित्र पर महिलओं के सुरक्षित 20
राजधानी में पिछड़ा वर्गों की कल्याणकारी योजनाएं 22
गतिविधियां 26

पंजाबी

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ 2015-16 1
ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਆਟੋ ਸੰਵਾਦ 8
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 10
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 12

اردو

1 ..... دہلی سرکار کا بجٹ 2015-16
8 ..... محکمہ ٹرانسپورٹ نے انعقاد آٹو مکالمہ
10 ..... دہلی کے وزیر اعلیٰ نے شروع کی بدعنوانی مخالف ہیلپ لائن
12 ..... سرگرمیاں

आज से
दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद !

एंटी करप्शन हेल्पलाइन नं. 1031

नमस्कार,

दिल्ली सरकार ने दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन–1031 शुरू की है। इसके जरिए सरकार ने आपको, यानि कि हर नागरिक को इंस्पेक्टर बना दिया है। अब अगर आपसे कोई सरकारी अफसर रिश्वत मांगे तो उसे मना मत करना। जब वो रिश्वत मांग रहा हो तो, अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पर लगा देना और उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना। फिर हमें 1031 पर कॉल करना। हम उस अफसर को रंगे हाथ पकड़ेंगे और जेल भेजेंगे।

हम सब मिलकर दिल्ली को भारत का पहला भ्रष्टाचार मुक्त शहर बनाएंगे। ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। आप सबका साथ चाहिए। मेरा साथ देंगे न।

जय हिन्द!

–अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार

DELHI GOVERNMENT
Team Delhi, Making things happen

मिलकर दिल्ली को खुशहाल बनाएंगे

दिल्ली सरकार का बजट 2015-16

दिल्ली के वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा में आप सरकार का पहला बजट प्रस्तुत किया

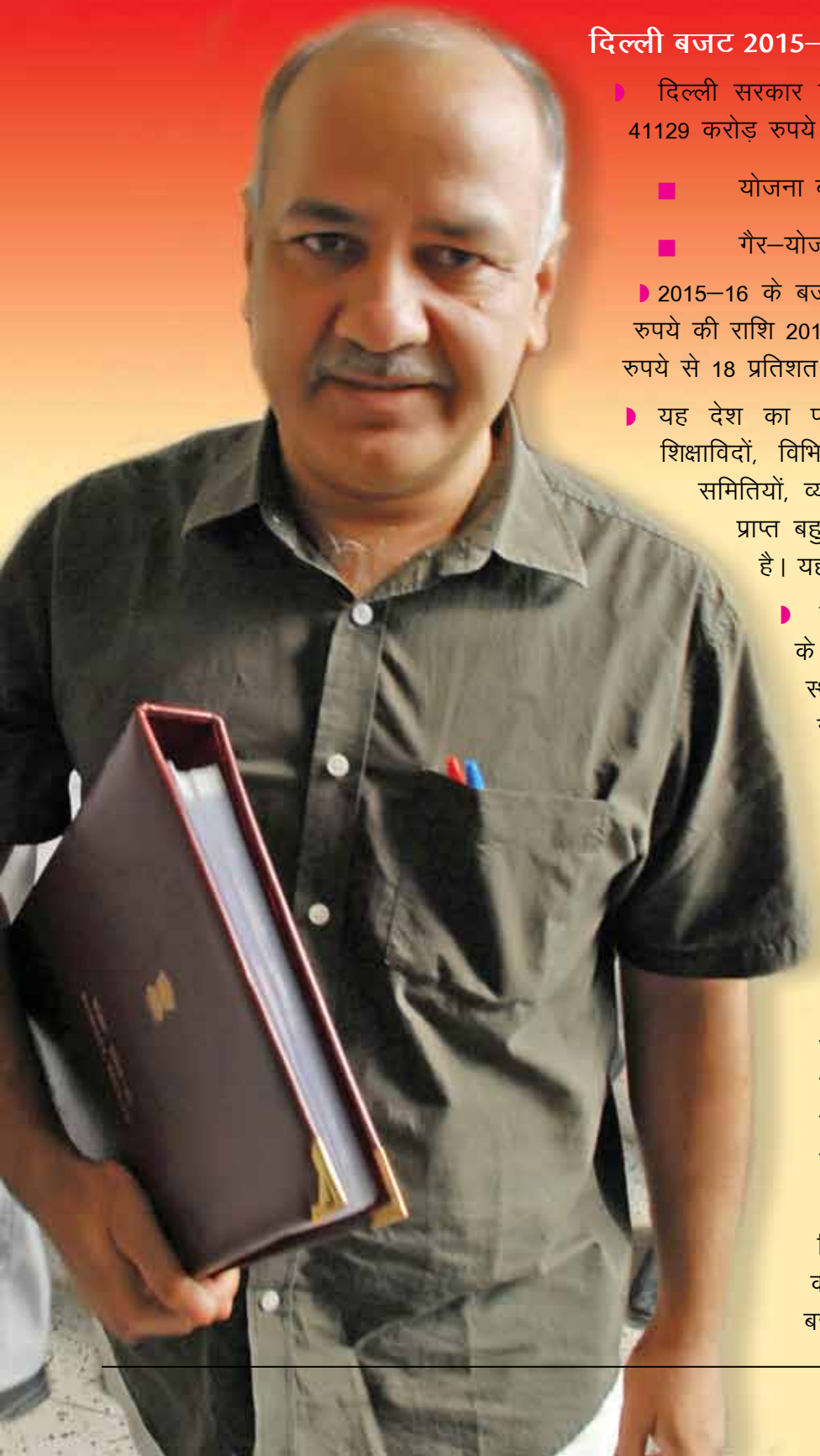

दिल्ली बजट 2015–16 की विशेषताएं

- दिल्ली सरकार का वर्ष 2015–16 के लिए कुल अनुमान 41129 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
  - योजना बजट – 19000 करोड़ रुपये
  - गैर–योजना बजट – 22129 करोड़ रुपये
- 2015–16 के बजट के लिए कुल प्रस्तावित 41,129 करोड़ रुपये की राशि 2014–15 के संशोधित अनुमान 34,790 करोड़ रुपये से 18 प्रतिशत अधिक है।
- यह देश का पहला 'स्वराज बजट' है, जो नागरिकों, शिक्षाविदों, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, RWAs, नागरिक समितियों, व्यापार संगठनों, कारपोरेट घरानों आदि से प्राप्त बहुमूल्य जानकारी और सुझावों पर आधारित है। यह भारत का प्रथम भागीदारीपूर्ण बजट है।
- एक नई पहल के रूप में 253 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ ''स्वराज निधि'' की स्थापना करने का प्रस्ताव है, जिसके जरिये नागरिक अपने क्षेत्र के विकास के लिए स्वयं चुने गए कार्यक्रमों को लागू कर सकेंगे।
- दिल्ली सरकार ने शासन की प्रक्रिया में नागरिकों को निर्णय करने का अधिकार प्रदान किया है।
- प्रत्येक राजस्व जिले में 'दिल्ली नगर विकास एजेंसी (डीयूडीए)' नाम की एक नई एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके माध्यम से नागरिकों द्वारा स्वराज फंड और माननीय विधायकों द्वारा एम.एल.ए. फंड के अंतर्गत अनुशंसित किए गए कार्यों को निष्पादित किया जायेगा।
- स्थानीय निकायों को 2015–16 में वित्तीय सहायता के रूप में कुल 5,908 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए है, जो कुल बजट का 14.4 प्रतिशत है।

- सरकार ने शहरी शासन प्रणाली और सार्वजनिक सेवाओं का वितरण सर्वाधिक पारदर्शी व सुचारु ढंग से करने की प्रक्रिया शुरु की है ताकि रिश्वत को समाप्त किया जा सके और दिल्ली को देश का प्रथम भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाया जा सके।
- एस.डी.एम. ऑफिस से विभिन्न तरह के प्रमाण–पत्र जारी करने में होने वाले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार ने ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाएं शुरु की हैं।
- सरकार ने बिजली के बिलों में कमी, नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक परिवार को हर महीने 20,000 लीटर पानी की निःशुल्क आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण उपाय किए हैं जिसके लिए 1690 करोड़ रुपये की सहायता का प्रस्ताव है।
- दिल्ली सरकार ने प्याज और आलू का सुरक्षित भंडार बनाने का निर्णय किया है और इन वस्तुओं की कमी होने की स्थिति में उन्हें बाजार में लाया जायेगा।
- 2015–16 में दिल्ली के सभी कालेजों और ग्रामीण क्षेत्रों को निःशुल्क वाई–फाई सेवा उपलब्ध कराई जायेगी।
- लाइसेंस देने की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा और तत्संबंधी प्रक्रिया को आसान बनाने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। यह समिति अपनी सिफारिशें 31 जुलाई, 2015 तक पेश करेगी।
- व्यापार करने में आसानी और शीघ्र निर्णय लेने के कारण दिल्ली जल्दी ही व्यापार के लिए सर्वाधिक वरीयता वाला स्थान बन जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विश्व की अन्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों में समन्वय करने के लिए वित्त एवं योजना विभाग के अंतर्गत एक प्रकोष्ठ बनाया जाएगा।

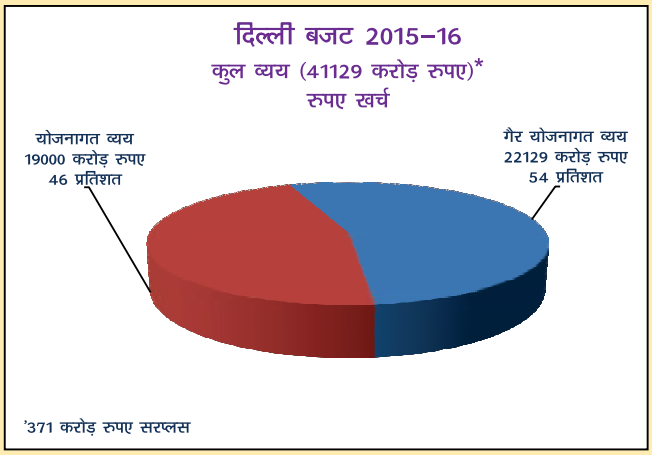

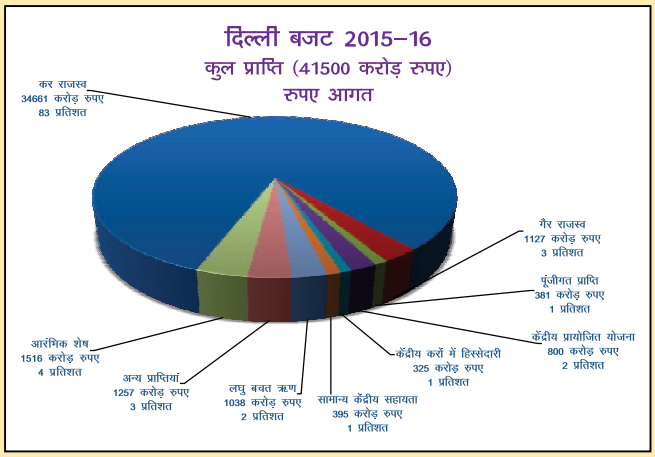

- शिक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। 2015–16 में इस क्षेत्र के लिए 4570 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। यह पिछले वर्ष के 2219 करोड़ रुपये के व्यय से 106 प्रतिशत अधिक हैं। यह देश में पहला अवसर है जब किसी सरकार ने शिक्षा के बजट में दो गुना बढ़ोत्तरी की है।
- सरकार की कार्यसूची में सभी 1011 सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है।
- आधुनिक सुविधाओं और ढांचे के साथ 50 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। तदुपरांत सभी स्कूल मॉडल स्कूल बन लाएंगे। 236 नए स्कूल खोलने की योजना है।
- सरकारी स्कूलों के सभी क्लासरूमों सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
- वर्ष के अत तक 20,000 नियमित शिक्षकों की भर्ती किए जाने की संभावना है ताकि विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात में सुधार लाया जा सके।
- उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी कार्यक्रम शुरु किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी बिना किसी कोलेटरल या मार्जिन राशि के 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
- महिला विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज की दर सामान्य ब्याज दरों से कम होगी।
- खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 'पे एंड प्ले' स्कीम यानी भुगतान करो और खेलों कार्यक्रम शुरु किया है जिसके अंतर्गत आम आदमी मामूली शुल्क अदा करके सरकारी खेल परिसरों और स्टेडियमों की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- दिल्ली सरकार व्यावसायिक और कौशल विकास में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये 310 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
- 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रत्येक विद्यार्थी को दो प्रमाण–पत्र एक सामान्य शिक्षा और दूसरा कौशल शिक्षा के लिए देने की योजना है।
- प्रत्येक पॉलिटैक्निक में 100 सीटों करने की योजना है।
- रन्होला, छतरपुर और बक्करवाला में 3 नए आईटीआई खोलने की योजना है। 5 नए पॉलिटेक्निक संस्थान – उत्तरी, उत्तर–पूर्वी मध्य, नई दिल्ली और पश्चिमी जिले में एक–एक खोलने की योजना है।
- नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान का उन्नयन एक विश्वविद्यालय के रूप में किया जाएगा, जिससे 5 वर्ष की अवधि में इस संस्थान में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाकर 12000 की जाएगी।
- अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में इन–क्युबेशन सैंटर स्थापित किये जायेंगे।
- नांगलोई, सिरसपुर और मादीपुर में कुल 1800 बिस्तर क्षमता के 3 नए खोलने की योजना है।
- 11 मौजूदा अस्पतालों को नया रुप देने और उनके उन्नयन की योजना है, जिससे अगले 2 वर्षों में इन अस्पतालों में 4000 नए बिस्तर जोड़े जाएंगे।

- सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान दिल्ली के सभी भागों में 500 ''मोहल्ला क्लिनिक'' खोलने की योजना बना रही हैं।
- मोहल्ला क्लिनिक में आने वाले रोगियों को निदानात्मक सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य दिल्ली में आधुनिक सुविधाओं के साथ 5 केंद्रीयकृत प्रयोगएशालाएं खोली जाएंगी।
- सरकार खेलों के दौरान घायल होने वाले खिलाड़ियों के पुनर्वास के लिए लोकनायक अस्पताल में एक अत्याधुनिक ट्रॉमा केयर सेंटर खोलने की योजना बना रही है जिसमें आईसीयू और ओटी सुविधाओं सहित 100 ट्रामा बिस्तरों की व्यवस्था होगी।
- आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क बिस्तर सुविधा के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था की जाएगी।
- स्वास्थ्य आंकड़े दर्ज करने और दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में पंजीकरण और उपचार का रिकॉर्ड रखने के लिए व्यक्तियों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे।
- धर्मार्थ क्लिनिकों/औषधालयों के जरिए दिल्ली के नागरिकों को निःशुल्क औषधियां प्रदान की जाएंगी।
- सरकार 2016 के अंत तक डीटीसी के लिये 1380 सेमी–लो–फ्लोर बसें, 500 मिडी बसें खरीदेगी और क्लस्टर स्कीम के अंतर्गत लगभग 1000 नई बसें शामिल करेगी।
- यात्रियों की अलग–अलग तरह की जरूरतें पूरी करने के लिए सार्वजनिक–निजी–भागीदारी क्लस्टर योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र से विभिन्न विशेषताओं वाली 10,000 बसें शामिल करने का प्रस्ताव है।
- एनसीआर के करीब 5500 नए ऑटो परमिट किए जा रहे हैं।
- करीब 1200 नए बस क्यू शेल्टर्स बनाने का प्रस्ताव है।
- चालू वर्ष में 64 मेट्रो फीडर मार्गों पर करीब 304 नई मिनी बसें शामिल करने का प्रस्ताव है।
- अंतिम मील तक यातायात उपलब्ध कराने के लिए सरकार दिल्ली में ई–रिक्शा को प्रोत्साहित कर रही है। ई–रिक्शा की खरीद पर 15,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- दिल्ली सरकार ने टैक्सियों और ऑटो सहित सभी सार्वजनिक वाहनों के लिए जीपीएस प्रणाली अनिवार्य कर दी है ताकि वाहनों की स्थिति का पता लगाया जा सके।
- सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव है।
- दिल्ली सरकार ने सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में मार्शल तैनात करने का फैसला किया है ताकि अपराध का भय समाप्त किया जा सके और महिला यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- वास्तविक समय सारणी उपलब्ध कराने के लिये यात्री सूचना प्रणाली शुरु की जायेगी।

- दिल्ली सरकार निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ कामकाजी महिलाओं के लिए 6 होस्टल बनाने की योजना बना रही है।
- सरकार स्लम और झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 300 शिशु सदन (क्रेच) सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बना रही है।
- चालू वित्त वर्ष के दौरान फेज–1 में कांतिनगर, चितरंजन पार्क, रोहिणी, पश्चिम विहार और छतरपुर में नए वृद्धावस्थ आश्रम का निर्माण कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है।
- दिल्ली सरकार ने ड्यूटी के समय बलिदान करने वाले रक्षा सैनिकों और अर्द्धसैनिक बलों के सदस्यों जो दिल्ली के निवासी हों, के परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने का निर्णय किया है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली होमगार्ड, दिल्ली सिविल डिफेंस कार्मिकों के मामले में ड्यूटी के दौरान बलिदान की स्थिति में समान मुआवजे की राशि अदा की जाएगी।
- सरकार ने अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि से फसल नष्ट होने की स्थिति में 20,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को अनुग्रह राशि देने का निर्णय किया है।
- निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को न्यूनतम अधिसूचित दिहाड़ी का भुगतान और बेहतर कल्याण सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए श्रमिक विकास मिशन प्रारंभ किया गया है।

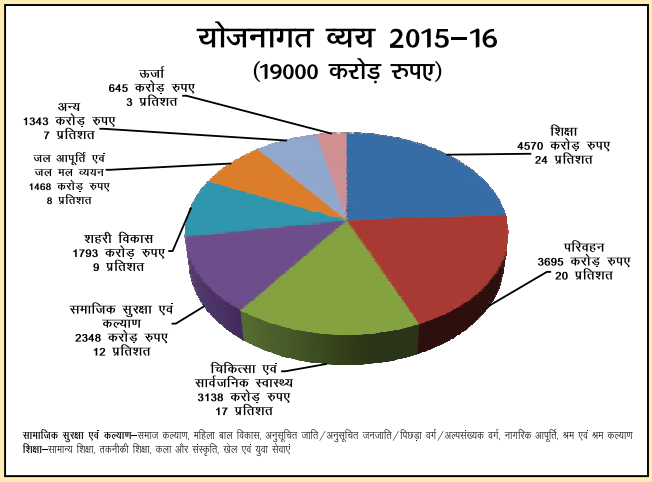

- शहर में पानी की बढ़ती मांग को पूरी करने के लिए पानी का उत्पादन बढ़ाने के वास्ते इरादत नगर में नया जल शोधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा और चंद्रावल तथा वजीराबाद स्थित जल शोधन संयंत्रों का जीर्णोद्धार किया जाएगा।
- ''वाटर टैंकरों पर सार्वजनिक निगरानी'' के लिए एक नया पोर्टल शुरु किया गया है ताकि लोग वाटर टैंकरों पर प्रभावी, सतत और कड़ी निगरानी रख सकें। 400 से अधिक टैंकरों में जीपीएस और वाटर सेंसर्स लगाए गए हैं और एक वेब आधारित प्रणाली के जरिए उनके संचालन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।
- ''जन जल–प्रबंधन योजना'' नाम का एक नया कार्यक्रम शुरु किया जाएगा जिसका उद्देश्य जल और सीवर सुविधाओं के प्रबंधन में विकेंद्रीकृत ढंग से समुदाय को शामिल करना है।

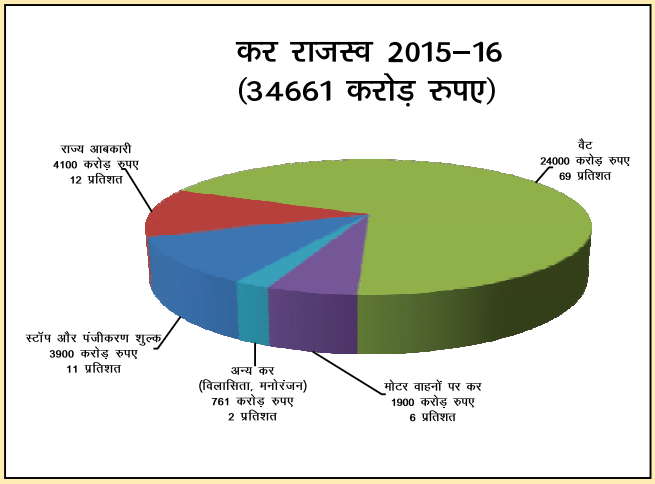

- नागरिकों का सक्षम और अनुकूल ढंग से जल एवं सीवर सेवाएं प्रदान करने के लिए ''स्वयं मीटर रीडिंग और बिल सृजन'' के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू किया जाएगा।
- दिल्ली में भविष्य में अनाधिकृत निर्माण को रोकने के लिए जीएसडीएल नियमित अंतराल पर उपग्रह चित्र आंकड़े राजस्व विभाग को प्रदान करेगा, जिनमें नए अतिक्रमण / अनाधिकृत निर्माण स्पष्ट रूप से रेखांकित किए जाएंगे ताकि उन्हें रोकने के लिए सम्बद्ध प्राधिकारी समुचित कार्रवाई कर सकें।

- चालू वित्त विर्ष के दौरान एक ऊर्जा सरंक्षण विधि की स्थापना की जाएगी ताकि ऊर्जा सक्षम परियोजनाओं और स्ट्रीट लाइटिंग आदि के लिए धन की व्यवस्था की जा सके।
- वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान सभी सम्बद्ध सरकारी एजेंसियों द्वारा 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बैटरी संचालित चार पहिए दुपहिया वाहनों की नई खरीद पर दिल्ली सरकार सब्सिडी प्रदान करेगी, जो केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त होगी।
- संभवतः भारत के इतिहास में यह प्रथम भागीदारी पूर्ण बजट है जिसमें जन साधारण की भागीदारी व्यय योजना तथा राजस्व को बढ़ाना दोनों में रही।
- एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में दिल्ली के वितरक स्वरूप को देखते हुए कर प्रबंधन में पारदर्शिता और स्थिर कर प्रशासन में पूर्वानुमेयमा को ध्यान में रखा गया है।
- कर क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के लिए व्यापारिक आसूचाएं एकत्रित करना ही लक्ष्य था। कर दरों में बदलाव को गौण रखा गया है।
- वैट राजस्व का लक्ष्य अनुमानित 24000 करोड़ रुपये है जो सरकार के कुल राजस्व संग्रह लक्ष्य का 69 प्रतिशत है।
- लक्कड़ तथा इमारती जो कि महत्वपूर्ण भवन निर्माण सामग्री है, इस पर वैट 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। चाकु–छुरी इत्यादि कटलरी वस्तुओं पर कर की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। प्रैशर कूकरों/कड़ाहियों जैसे अन्य रसोई के बर्तनों पर इतना ही है।
- अब सभी प्रकार के मोम पर वैट की दर 12.5 प्रतिशत रहेगी। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के मोम (वैक्स) पर क्रमशः 5 प्रतिशत, 12.5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया जाता है। इसमें मोम की वैट दरों में अस्पष्टता समाप्त हो जाएगी।
- सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की बसों तथा दिल्ली में प्रवेश करने वाली टैक्सियों को छोड़कर डीजल से चलने वाले व्यावसायिक वाहनों पर 100 से 1500/– रुपये के शुल्क की वसूली ताकि दिल्ली में परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार के लिये पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, वे–इन–मोशन पुलों की संस्थापना तथा अन्य उपाय किये जा सकें।

- शराब पर आबकारी शुल्क संग्रह पद्धति में भारी बदलाव करते हुए परिवहन परमिट स्तर से आयात परमिट स्तर पर अंतरित करने का प्रस्ताव किया गया है। आबकारी शुल्क में परिवर्तन न करते हुए केवल लाइसेंस शुल्कों में बढ़ोतरी की जा रही है।
- दिल्ली मीडियम लिक्कर के अप्रचलित ब्रैंड को वर्ष के दौरान चरणबद्ध तरीके से हटाने का प्रस्ताव है।
- विभिन्न आबकारी लाइसेंसों के नवीकरण की प्रक्रिया में सुधार करते हुए सरल बनाया जा रहा जिससे इस प्रक्रिया में लगने वाले समय में कटौती होगी।
- सभी प्रतिष्ठानों पर लागू विलासिता कर की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की जायेगी।
- मनोरंजन कर, केबल टी.वी./डी.टी.एच. सेवाओं पर 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये करने तथा सिनेमाघरों में टिकटों पर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
- कंपनियों तथा भागीदारी फर्मों के नाम पर पंजीकृत सभी निजी वाहनों के पंजीकरण कर में विद्यमान दरों पर 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा रही है।
- भारतीय स्टाम्प अधिनिमय में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि जुर्माने की दर विलम्ब के प्रत्येक महीने के लिये कमी राशि के 2 प्रतिशत की दर से युक्तिसंगत बनाई जाये। वर्तमान में, 5 रुपये से स्टाम्प ड्यूटी में कमी की मात्रा के 10 गुना तक, जुर्माना लग सकता है।
- अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक दृष्टि से पारदर्शी बनाने के लिये इसके कुछ अन्य प्रावधानों में संशोधन किया जाये।
- दिल्ली के कृषि भूमि के सर्कल रेट विद्यमान 53 लाख रुपये से बढ़ाकर राजस्व जिलों के अनुसार 1 करोड़ से 1.5 करोड़ करने का प्रस्ताव है।
- ऐसी कृषि भूमि जिनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण की लैंड पूलिंग नीति लागू है कृषि भूमि की पृथक श्रेणी होगी जिसकी सर्कल दरों में राजस्व जिले के अनुसार 2.25 करोड़ रुपये से 3.5 करोड़ रुपये की सीमा तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। ■

परिवहन विभाग ने आयोजित किया

ऑटो संवाद

दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने परिवहन विभाग की ओर से दिल्ली परिवहन अथारिटी के नजदीक बुराड़ी मैदान में आयोजित ऑटो संवाद में ऑटो रिक्शा चालकों को संबोधित किया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री श्री गोपाल राय, समाज कल्याण मंत्री श्री संदीप कुमार, विधायक, परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न संघो के सदस्य मौजूद थे। श्री केजरीवाल ने बताया कि सरकार ऑटों रिक्शा चालकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को शुरू कर रही है।

परिवहन मंत्री श्री गोपाल राय ने बताया कि परिवहन विभाग ने काम से घर लोट रहे ऑटो चालको के लिए एक साइनेज प्रणाली की शुरूआत की है जिससे यात्रियों

को सुविधा के साथ साथ ऑटो चालकों को चलान से भी मुक्ति मिलेगी। इसके तहत रात में अपने घर जा रहे ऑटो चालक अपने ऑटों पर एक डिजिटल साइनेज बोर्ड लगाएगा, जिसमें उस रास्ते का जिक्र होगा जिससे वह ऑटो चालक गुजरेगा इससे किसी भी ऑटो चालक पर यह कहकर कि उसने जाने से इंकार कर दिया उस पर जर्माना नहीं किया जा सकेगा और यात्रियों को भी आसानी से पता चल जाएगा कि यह ऑटों किस रास्ते से जाएगा।

ऐसे 4 वेंडरों जो जीपीएस लगाने के लिए 10,000 रुपए से कम ले रहे हैं, की सूची डिम्ट विभाग द्वारा परिवहन विभाग की साइट पर डाल दी गई है। डिम्ट विभाग ने इसका व्यापक प्रचार भी किया गया है। डिम्ट ने जीपीएस हैल्पलाइन नम्बर 9311900800 जारी किया है, जिस पर जीपीएस संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

राजधानी में विभिन्न जगहों पर ऑटो रिक्शा स्टैंडों बनाए जा रहे है जहां 'हेल्ट एंड गो प्रणाली' के तहत ऑटों रिक्शा चालक अपना ऑटों खड़ा कर सकेगा। इसके लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इन स्टैंडों पर खड़े होने पर किसी भी ऑटों चालक पर जुर्माना नहीं लागाया जा सकेगां। परिवहन विभाग की ओर से जारी यात्री हैल्पलाइन न. 42400400 पर प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई की जानकारी यात्रियों को भी दी जाएगी।

इस अवसर पर श्री संदीप कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक एवं विक्लांग वित्तीय विकास निगम दिल्ली स्वरोजगार योजना के तहत कमर्शियल गाड़ी खरीदने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक एवं विक्लांग श्रेणी के व्यक्तियों को 5 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया करा रहा है। ■

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शुरू की भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन

दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल ने तालकटोरा स्टेडियम के सभागार में एक भव्य समारोह में भ्रष्टाचार विरोधी हेल्प लाइन शुरू की। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली से भ्रष्टाचार पूरी तरह मिटाने का एलान करते हुए कहा कि अगले 5 वर्ष में दिल्ली को देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति भी यदि भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो उसे जेल भेजा जायेगा।

उन्होंने दिल्ली की जनता से एक बार फिर अपील की कि यदि उनसे कोई रिश्वत मांगता है तो मना न करें और

1031

भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर

रिश्वत मांगने वाले की आवाज रिकार्ड कर लें या फिर वीडियो बना लें। उन्होंने कहा कि रिकार्डिंग करने के बाद भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन 1031 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। ऐसे में शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

श्री केजरीवाल ने कहा कि पिछले वर्ष की 49 दिन की सरकार का कामकाज देखकर ही दिल्ली की जनता ने उन्हें 67 सीटें देकर प्रचण्ड बहुमत दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार झूठे वादे नही करती बल्कि अपने वादों को पूरा करती है। उन्होंने बताया कि बिजली के पुराने बिलों को ठीक करने की योजना भी बनाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि समूचे विश्व में भारत के लोग नाम कमा कर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहें हैं लेकिन अपने देश में आकर विफल हो जाते हैं क्योंकि यहां भ्रष्टाचार है। श्री केजरीवाल ने कहा कि सरकार अगले पांच वर्ष में दिल्ली को देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के साथ साथ दिल्ली को विश्व के 5 टाप भ्रष्टाचार मुक्त शहरों में शामिल करा देगी।

उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे अपने कार्यालयों में लोगों को अपने साथ मोबाइल लाने की अनुमति दें ताकि लोग रिश्वत मांगने पर रिकार्डिंग कर सकें। उन्होंने अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि यदि वह ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो कोई गलती हो जाने पर भी वह चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहेंगे लेकिन यदि भ्रष्टाचार करेंगे तो अन्त तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे।

उन्होंने कहा कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा तथा मौजूदा कानूनों को सरल बनाया जाएगा।

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के मुख्य सचिव श्री के.के. शर्मा, प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव श्री अरुण बरोका ने भी उपस्थित व्यक्तियों को सम्बोधित किया। इस कार्यक्रम के अंत में सचिव जनसम्पर्क श्री सज्जन सिंह यादव ने अंत में सभी का आभार व्यक्त किया। ■

श्री केजरीवाल ने कहा कि पिछले वर्ष की 49 दिन की सरकार का कामकाज देखकर ही दिल्ली की जनता ने उन्हें 67 सीटें देकर प्रचण्ड बहुमत दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार झूठे वादे नही करती बल्कि अपने वादों को पूरा करती है। उन्होंने बताया कि बिजली के पुराने बिलों को ठीक करने की योजना भी बनाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि समूचे विश्व में भारत के लोग नाम कमा कर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहें हैं लेकिन अपने देश में आकर विफल हो जाते हैं क्योंकि यहां भ्रष्टाचार है। श्री केजरीवाल ने कहा कि सरकार अगले पांच वर्ष में दिल्ली को देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के साथ साथ दिल्ली को विश्व के 5 टाप भ्रष्टाचार मुक्त शहरों में शामिल करा देगी।

जापानी प्रतिनिधिमंडल के छह सदस्यों ने की दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात

जापान के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जापान के पूर्व वित्त मंत्री श्री कोजी आमी के नेतृत्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया से दिल्ली सचिवालय में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत में जापान के राजदूत श्री तकशी यागी भी उपस्थित थे। इस मुलाकात का केन्द्र बिन्दु लोगों के दैनिक जीवन में विज्ञान और तकनीकी का महत्व था।

श्री कोजी ऑमी ने जापान में अक्तूबर, 2015 में होने वाली एसटीएसी फोरम कांफ्रेंस के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल को आमंत्रित किया। श्री केजरीवाल ने आमंत्रण के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। श्री केजरीवाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि या तो वे खुद या दिल्ली के उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया इस कांफ्रेंस मे हिस्सा लेंगें। उन्होंने कहा हमारी सरकार विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से दिल्ली के लोगों के दैनिक जीवन में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत में जापानी राजदूत श्री ताकेशी यागी ने मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया से कहा कि हमें विश्वास है कि दिल्ली में लगभग 3000 जापानी नागरिकों और जापानी कंपनियों को दिल्ली सरकार द्वारा पूरा सहयोग और सुरक्षा दी जाएगी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने जापानी प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जापनी कम्पनियों और उसके नागरिकों को दिल्ली सरकार द्वारा पूरी सुरक्षा और जरूरी मदद मुहैया कराई जाएगी। ■

- **जापानी प्रतिनिधिमंडल ने जापान में अक्तूबर माह में होने वाली एसटीएसी फारम कांफ्रेंस के लिए मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल को आमंत्रित किया**
- **मुख्यमंत्री ने जापानी प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि एसटीएसी फारम कांफ्रेंस में नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व जरूर होगा**

दिल्ली जलबोर्ड ने उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क के लिए एसएमएस की शुरुआत

दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी के उपभोक्ताओं से सीधे जुड़ने और उनकी समस्या का हल करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लिया है। अब दिल्ली जलबोर्ड एसएमएस सुविधा के जरिए अपने उपभोक्ताओं से लगातार संपर्क में रहेगा। इस सुविधा से दिल्ली के 21 लाख से ज्यादा उपभोक्ता को फायदा होगा। यह बात दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सज्जन सिंह यादव ने बताई।

श्री सज्जन सिंह यादव ने बताया कि उपभोक्ताओं को दिल्ली जल बोर्ड की नियमित जानकारी पाने के लिए अपने मोबाईल नम्बर को पानी के मीटर के 10 अंक वाले के. नंबर से लिंक करना होगा। एसएमएस द्वारा या जलबोर्ड के वैबसाईट www.djb.gov.in द्वारा अपने मोबाईल नम्बर को पंजीकृत कराया जा सकता है। एसएमएस द्वारा रिजस्टर करने के लिए उपभोक्ता अपने मोबाईल नंबर से DJBIN <space> <10 DIGIT K NO.> लिख कर जलबोर्ड के नंबर 7738299899 पर रजिस्टर करन होगा। श्री सज्जन सिंह यादव ने बताया कि अब जलबोर्ड का कोई भी उपभोक्ता अपने बिल, भुगतान अथवा बकाया राशि/बिल की जानकारी अपने रजिस्टर मोबाईल फोन से मात्र एक एसएमएस भेज कर प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा बकाया बिल के भुगतान की जानकारी एसएमएस अलर्ट द्वारा उपभोक्ताओं को नियमित रूप से दी जाएगी। श्री यादव ने आगे बताया कि इस एसएमएस सुविधा द्वारा उपभोक्ताओं को वाटर हार्वेस्टिंग (संचयन) तथा जल संरक्षण के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। इसके द्वारा पाइप लाइन में किसी खराबी अथवा जलापूर्ति बाधित होने की सूचना भी समय पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा सकेगी। साथ ही साथ जल निकासी और ड्रेनेज संबंधित कोई सूचना तथा नई योजना की जानकारी देने के लिए एसएमएस सुविधा काफी उपयोगी साबित हो सकता है।

दिल्ली जल बोर्ड ने अपने सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे यथा शीघ्र अपने मोबाईल न. और मीटर के. नंबर को जल बोर्ड के वैबसाईट अथवा एसएमएस द्वारा रजिस्टर कराएं ताकि बिलों की प्राप्ति से संबंधित शिकायतों तथा भुगतान से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके और साथ ही भविष्य में इस शिकायत से निजात पाया जा सके। किसी भी तरह की जानकारी के लिए उपभोक्ता दिल्ली जल बोर्ड के टोल फ्री न. 1916 पर डायॅल कर सकते हैं। श्री यादव ने दिल्ली जलबोर्ड के राजस्व विभाग के इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सुविधा उपभोक्ताओं के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। इस सुविधा से न केवल उभोक्ता दिल्ली जलबोर्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकंगे बल्कि बिलों की प्राप्ति और उनके भुगतान संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। ■

केजरीवाल सरकार के विभिन्न कार्यों की झलकियां

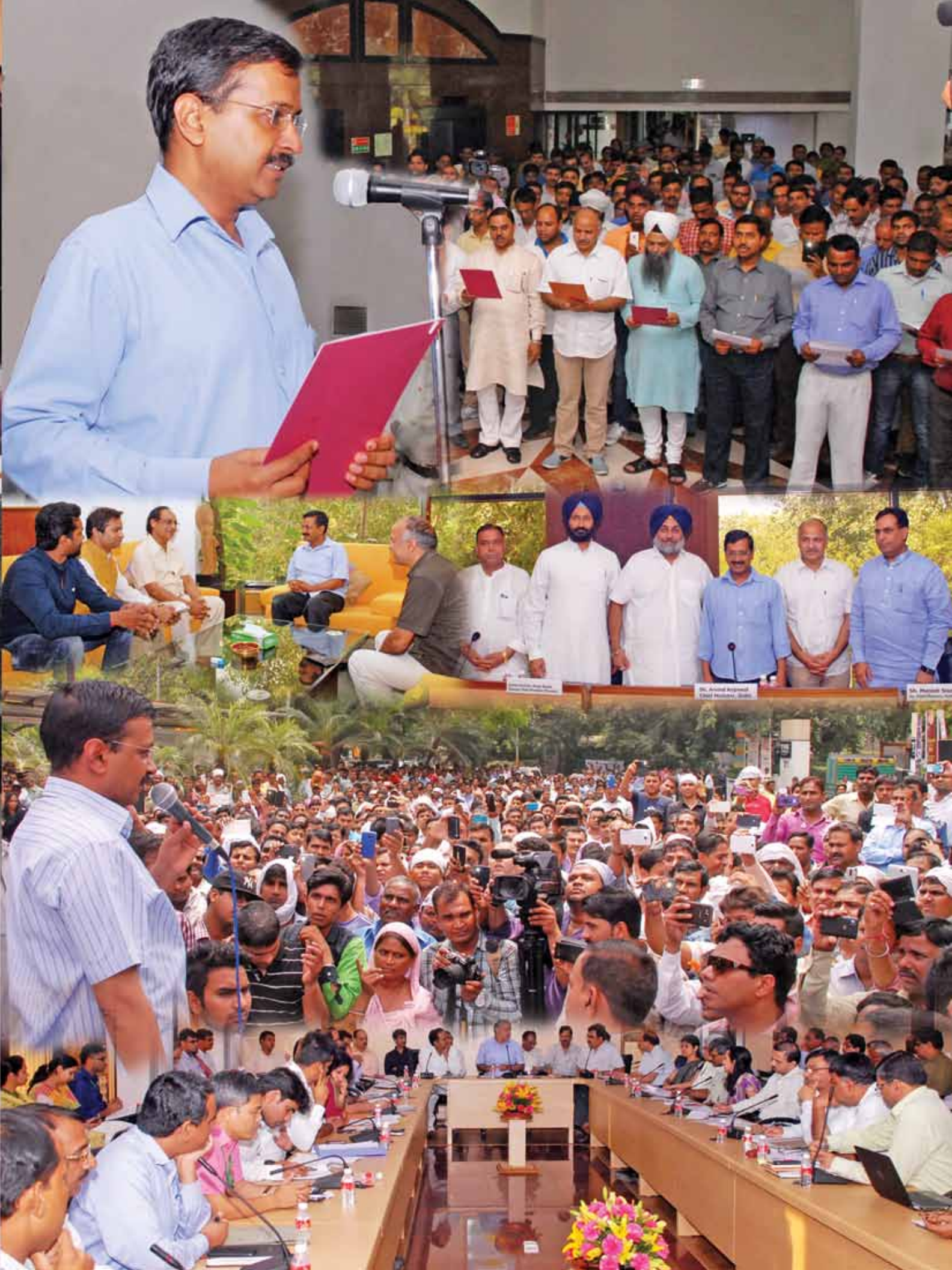

दिल्ली जलबोर्ड ने राजधानी के अनधिकृत कॉलोनी के निवासियों को विकास शुल्क में बड़ी राहत दी

दिल्ली सरकार राजधानी के अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को पानी एवं सीवर के इस्तेमाल के एवज में दिए जाने वाले विकास शुल्क के भुगतान में भारी छूट प्रदान दी है। दरअसल दिल्ली जलबोर्ड ने विकास शुल्क में बड़ी राहत (लगभग 80:) प्रदान करने की एक योजना शुरू की है। इस योजना में अनधिकृत कॉलोनियों (डी, ई, एफ, जी और एच श्रेणी) में विकास शुल्क अब मात्र 100 रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से लगेगा जबकि पूर्व में पानी के लिए 440 रु – सीवर के लिए 494 रु. sq. mtr. था। यह योजना अधिसूचना की तारीख यानी 26.06.2015 से तीन महीने के लिए उपलब्ध रहेगा। यह जानकारी दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ, श्री सज्जन सिंह यादव ने प्रदान की।

श्री सज्जन सिंह यादव ने बताया कि राजधानी के ई, एफ, जी और एच श्रेणी के अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को 200 वर्ग मी. तक के क्षेत्र के आवासीय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे घरेलू और मिश्रित उपयोग श्रेणी के भूखंडों के लिए विकास शुल्क कम मात्र 100 रु. प्रति वर्ग मीटर (अलग से पानी और सीवर के लिए) कर दिया गया है। यह दर वाणिज्यिक और संस्थागत मामलों के लिए और 200 वर्ग से बडे भूखंडों के लिए भूखंडों के संबंध में लागू नहीं होगी। निर्धारित अवधि के भीतर इस सुविधा का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं को विकास शुल्क के भुगतान में लगभग 80: की राहत मिलेगी।

श्री यादव ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को बुनियादी सुविधा यथा पानी की उपलब्धता और सीवर लाईन बिछाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा विकास शुल्क लिया जाता है. समय–समय पर संशोधित दरों के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड द्वारा यह शुल्क लगाया जाता है। वर्तमान में यह विकास प्रभार की दर 440 रु. और 494 रु. प्रति sq. mtr. (क्रमशः पानी और सीवर के लिए) है। अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों खास कर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग, जो विकास शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ थे, पानी और सीवर विकास शुल्क के भुगतान में राहत की मांग कर रहे थे।

यह योजना लागू कर दिल्ली सरकार अपने वादे को पूरा किया है जैसा कि चुनाव घोषणा पत्र में इन कॉलोनियों के निवासियों को राहत प्रदान करने का आश्वासन दिया था।

श्री सज्जन सिंह यादव ने आगे बताया कि इस योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगा जिन्होंने विकास शुल्क का आंशिक भुगतान किया है और यदि यह भुगतान वर्तमान विकास शुल्क यानि 100 प्रति Sq. mtr. से कम है। इस स्थिति में उन्हें सिर्फ फर्क यानी शेष धनराशी ही जमा करना होगा। जो उपभोक्ता पहले से ही के बराबर या उससे अधिक राशि जमा कर चुके है या जहां आंशिक भुगतान के मामलों के लिए 100 प्रति Sq. mtr. से अधिक का भुगतान कर चुके हैं, उन्हें आगे कोई भुगतान किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही यदि अतिरिक्त राशि पहले से ही भुगतान कर दिया गया है तो वे वापसी के लिए पात्र नहीं होंगे।

श्री यादव कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने सभी अनधिकृत पानी के कनेक्शनों को नियमित करने के लिए एक उदारीकृत योजना का भी शुभारंभ किया है। घरेलू उपभोक्ताओं का अनधिकृत पानी कनेक्शन 18000 रुपये के बजाये मात्र 3310 रुपये के भुगतान पर नियमित हो सकता है। वाणिज्यिक उपभोक्ताओं का अनधिकृत पानी कनेक्शन भी इस योजना के तहत नियमित किया जा सकता है। यह योजना 27.08.2015 तक चालू रहेगी।

हालांकि, इस तरह अनधिकृत पानी के कनेक्शनों को नियमित करने के लिए तकनीकी व्यवहार्यता और दिल्ली जल बोर्ड के जलवितरण प्रणाली अधिसूचित और वृत्तचित्र/औपचारिकताओं/शर्तों को पूरा करने के उपरांत ही किया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड के सी. ई. ओ. श्री सज्जन सिंह यादव ने दिल्ली जल बोर्ड के इन योघ्नाओं के प्रति राजधानी के अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों की तरफ से भारी उत्साह की उम्मीद व्यक्त की है। जल बोर्ड के कार्यालयों में भारी भीड़ की उम्मीद को मद्देनज़र रखते हुए और तेजी से मामले के निपटारे के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने ना सिर्फ प्रक्रिया को सरल बनाया गया है बल्कि बल्कि सभी क्षेत्रीय राजस्व कार्यालयों में भी विशेष व्यवस्था की गयी है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उपभोक्ता दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट यानी www.djb.gov.in या www.delhijalboard.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या क्षेत्रिय कार्यलयों में भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए संपत्ति के कागजात, निवास के प्रमाण (यदि उपलब्ध हो) – उपभोक्ताओं को विधिवत आवेदन फार्म में पासपोर्ट आकार का फोटो सहित, अन्य पहचान का सबूत, स्वामित्व के प्रमाण की जरूरत है। यदि कोई उपभोक्ता पहले ही विकास शुल्क का पार्ट पेमेंट कर चुका है तो उन्हें उसकी रसीद की प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिससे कि उपभोक्ता को समुचित लाभ प्राप्त हो सके। ■

दिल्ली जल बोर्ड के सी. ई. ओ. श्री सज्जन सिंह यादव ने दिल्ली जल बोर्ड के इन योघ्नाओं के प्रति राजधानी के अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों की तरफ से भारी उत्साह की उम्मीद व्यक्त की है। जल बोर्ड के कार्यालयों में भारी भीड़ की उम्मीद को मद्देनज़र रखते हुए और तेजी से मामले के निपटारे के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने ना सिर्फ प्रक्रिया को सरल बनाया गया है बल्कि बल्कि सभी क्षेत्रीय राजस्व कार्यालयों में भी विशेष व्यवस्था की गयी है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उपभोक्ता दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट यानी www.djb.gov.in या www.delhijalboard.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या क्षेत्रिय कार्यलयों में भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए संपत्ति के कागजात, निवास के प्रमाण (यदि उपलब्ध हो) - उपभोक्ताओं को विधिवत आवेदन फार्म में पासपोर्ट आकार का फोटो सहित, अन्य पहचान का सबूत, स्वामित्व के प्रमाण की जरूरत है।

दिल्ली को अगले पांच साल में दुनिया के मानचित्र पर महिलाओं के लिए सुरक्षित शहरों में शुमार करने का संकल्प

राजधानी की महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उनके खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम दिल्ली सरकार के एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण है। दिल्ली में महिला सुरक्षा के विचार को राजधानी की सांस्कृतिक विरासत और गरिमामयी महानगर बनाने के संकल्प से जोड़कर देखे जाने की आवश्यकता है। ऐसे में, महिलाओं को सिर्फ सुरक्षित दिल्ली देने की जरूरत है क्योंकि वे स्वयं अपना और दिल्ली का विकास करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्री संदीप कुमार ने संयुक्त राष्ट्र महिला के सुरक्षित नगर पर वैश्विक नेताओं के फोरम की ओर से महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित नगर विषय पर आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही।

श्री संदीप कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं के जुड़े अपराधों पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक स्थलों को सुरक्षित करने की कवायद शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार इस मुश्किल काम को पूरा करके दिखाने के लिए कृत संकल्प है। ऐसे में, यूएन वूमैन का सेफ सिटी प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण चरण है। उन्होंने कहा कि मैं आज इस मंच से यूएन वूमेन और इससे जुड़ी विभिन्न संस्थाएं जो दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए कार्यरत हैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम साथ मिलकर इस लक्ष्य को हासिल करेंगे और पांच साल में दिल्ली को दुनिया के मानचित्र पर महिलाओं के लिए सुरक्षित शहरों में शुमार करके ही दम लेंगे।

दिल्ली के महिला बाल विकास मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर जनता से सीधे संवाद

स्थापित करने की ओर कदम बढ़ाए हैं। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों, जिन पर सरकार ने गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया है, में सबसे पहला सार्वजनिक यातायात को सुरक्षित बनाने का है। इसके लिए, दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में प्रथम चरण में 4000 मार्शल नियुक्त करने की तैयारी कर ली है। प्रायोगिक चरण में 200 बसों में सीसीटीवी कैमरे और 120 मार्शलों की नियुक्ति की जा चुकी है। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने सभी सार्वजनिक वाहनों विशेषकर टैक्सी वाहनों में जीपीएस प्रणाली को लगवाना अनिवार्य कर दिया है, जिससे इन वाहनों पर हर परिस्थिति में निगरानी की जा सके । सरकार ने इसी दिशा में स्थापित मानकों पर खरा न उतरने के कारण कड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ मोबाईल एप आधारित टैक्सी सेवाओं पर रोक लगाई है।

श्री संदीप कुमार ने कहा कि दिल्ली को सुरक्षित शहर बनाने के लिए सरकार ने दिल्ली पुलिस को डार्क स्पॉट (अंधेरे–सुनसान स्थान) चिन्हित करने के लिए कहा गया है, जिससे इन स्थानों को लेकर सुरक्षित इंतजाम किए जा सकें। इसके साथ ही राजधानी के 44 पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले अति संवेदनशील स्थानों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए भी कहा है। सरकार ने दिल्ली पुलिस से लड़कियों के स्कूल, महिला महाविद्यालयों सहित कम रोशनी वाले स्थानों पर पीसीआर वैनों की तैनाती सुनिश्चित करने को भी कहा है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर अपराधियों को सजा दिलाने में एक लंबा समय लग जाता है। ऐसे में, दिल्ली सरकार ने 20 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने जा रही है, जो अपराधी को कम समय में सख्त सजा दिलावाने की बात को सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के बारे को मानसिकता से जोडकर भी देखने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस विषय में जन–जागरण अभियान चलाने की तैयारियां की हैं। उन्होंने बताया कि जन–संचार के माध्यमों को सहयोग लेकर समाज में बढ़ रही आपराधिक मानसिकता को समाप्त करने और अच्छे संस्कारों के प्रचार–प्रसार का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पुरूषों और लड़को को समाधान का हिस्सा बनाने के लिए यूएन वूमैन के साथ एक साझा कार्यक्रम भी बनाने जा रहे हैं।

श्री संदीप कुमार ने कहा कि सरकार महिलाओं से जुड़े मुद्दों के लिए हर स्तर पर पहल करने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि हमें अपने देश का इतिहास याद रखना चाहिए, जहां महिलाओं को नारी नहीं नारायणी के रूप में पूजा गया है। उन्होंने जन साधारण से लेकर इस विषय से जुड़े व्यक्ति और संस्थाओं से सुझाव के साथ–साथ पहल की भी अपेक्षा रखने की बात को रेखांकित करते हुए इस गंभीर विषय पर एकजुटता से कार्य करने की बात कही। ■

श्री संदीप कुमार ने राजधानी में पिछड़ा वर्गों की कल्याणकारी योजनाओं की पुस्तिका का विमोचन किया

दिल्ली के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री श्री संदीप कुमार ने यमुना विहार में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से दिल्ली सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों के पिछड़ा वर्गों के उत्थान के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी देने के लिए आयोजित जन–चेतना शिविर में एक पुस्तिका का विमोचन किया।

इस अवसर पर श्री संदीप कुमार ने कहा कि मुझे आशा है कि इस पुस्तिका में अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े लोगों के कल्याणार्थ सरकारी योजनाओं का समावेश अर्द्ध–सम्पन्न वर्ग के अलावा विशेषकर निर्धनता में जीवनयापन कर रहे लोगों की जानकारी एवं उनके स्वावलंबन की दिशा में एक सार्थक कदम होगा। जिससे इन लोगों को अपना जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब तक अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को ऐसी योजनाओं की उचित जानकारी नहीं होगी, वे इससे फायदा नहीं उठा सकेंगे।

उन्होंने आशा जताई कि दिल्ली सरकार का अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इस प्रकाशन के माध्यम से सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को जन–जन तक पहुंचाने में सफल होगा। उन्होंने कहा कि आयोग का भी यही मकसद है कि सरकारी सुविधाएं इस वर्ग के अधिक–से–अधिक लोगों तक पहुंचे, जिससे उनका जीवन स्तर सुधर सकें और इस वर्ग का उत्थान हो सकें। इस आयोग का मुख्य कार्य अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची में शामिल किए जाने के अनुरोधों और अधिक समावेश तथा कम–समावेश की शिकायतों पर ध्यान देने, जांच करने और सिफारिश देना है। इसके अलावा, इस प्रकार की सलाह सरकार को देना, जिसे वह उचित समझता है, इसका कार्य है।

दिल्ली के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री ने कहा कि आज के इस जन–चेतना शिविर में दिल्ली सरकार के अनेक विभागों के अधिकारी, नागरिकों के कार्य के लिए एक ही छत के नीचे एकत्र हुए हैं जो राजधानी के अन्य पिछड़ा वर्ग सहित दूसरे नागरिकों की समस्याओं का समाधान करेंगे।

उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग इस तरह के आयोजन हर विधानसभा क्षेत्र में करेंगा, जिससे अधिक से अधिक नागरिक विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। अब तक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने रोहिणी, खजूरी खास, ओखला, बागडोला गांव (द्वारका), तुर्कमान गेट और कोटला गांव (पटपटगंज) में ऐसे छह जन–चेतना शिविर आयोजित किए हैं।

श्री संदीप कुमार ने कहा कि राजधानी में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की समय–सीमा (कट–ऑफ) तिथि 1993 से आगे बढ़ाने की है, जिससे अधिक से अधिक संख्या में नागरिक अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवाने में सक्षम हो सकें। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से अन्य पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोग के समक्ष यह विषय उठाने की अपील की, जिससे राष्ट्रीय आयोग केंद्र सरकार को इस संबंध में आवश्यक नोटिफिकेशन जारी करने की में सलाह दे सकें।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं में प्रमुख रूप से विद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को लेखन सामग्री की निशुल्क आपूर्ति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए योग्यता छात्रवृत्ति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए डॉ भीमराव आंबेडकर राज्य पुरस्कार, पब्लिक स्कूलों में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पूर्व परीक्षा कोचिंग, शिक्षा ऋण योजना और छात्रावास सुविधाओं के अलावा स्वरोजगार के लिए ऋण योजनाएं शामिल है।

इस अवसर पर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह मावी, अंशकालिक गैर–सरकारी सदस्य श्री प्रवीन भाटी, पदेन सदस्य डॉ. सुदर्शन पाठक सहित विभाग के प्रधान सचिव श्री संजय प्रताप सिंह ने भी जन–चेतना शिविर में उपस्थित नागरिकों को संबोधित किया। ■

राजधानी से बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए

सरकारी-गैर सरकारी संगठनों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता

दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्री संदीप कुमार ने कॉस्टिटूशन क्लब में आयोजित एक समारोह में गैर सरकारी संगठन सेव–द–चिल्डर्न की "ए स्टडी ऑन चाइल्ड लेबर इन द गारमेट इंडस्ट्री इन दिल्ली" नामक रिपोर्ट का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री संदीप कुमार ने कहा कि राजधानी में बाल सुरक्षा को लेकर सेव–द–चिल्डर्न गंभीरतापूर्वक प्रयासरत हैं और आज जब मुझे इस बात की जानकारी मिला कि सेव–द–चाइल्ड बाल मजूदरी को लेकर एक अध्ययन किया है तो मेरे मन में स्वाभाविक रूप से यह इच्छा हुई कि दिल्ली में कितने बच्चे ऐसे हैं जो बाल मजदूरी के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली में अभी बच्चों की एक बड़ी आबादी सुरक्षित वातावरण सहित मूलभूत शिक्षा से वंचित है।

उन्होंने कहा कि बच्चों को सुरक्षित और आवश्यक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में दो स्तरों पर काम करने की जरूरत है। पहला, इस दिशा में सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों को संयुक्त रूप से प्रयास करने और दूसरा समाज के हर तबके में बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर समाज में एक संवेदनशीलता की भावना को जागृत करने की जरूरत है। इस विषय में संवेदनशील होने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि बच्चे ही भविष्य के नागरिक हैं, यही हमारा समाज बनेंगे और हमारा समाज बनायेंगे भी।

दिल्ली के महिला बाल विकास मंत्री ने कहा कि आज समय की मांग है कि बच्चों को सुरक्षित शिक्षित भविष्य देने के लिए बाल मजदूरी से जुड़े कानून को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि चूड़ी उद्योग, चटाई उद्योग और कपड़ा उद्योग में बड़ी संख्या में मजदूरी के लिए बच्चों

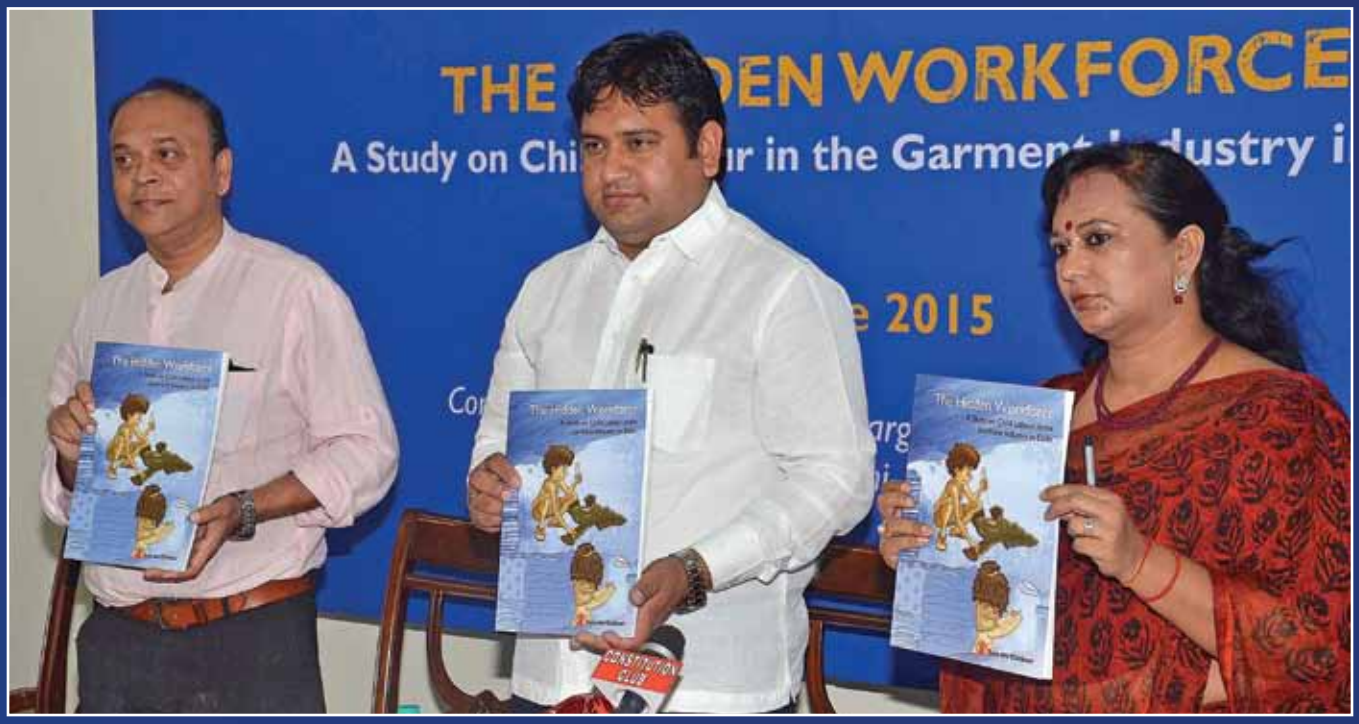

से काम लिया जाता जाता है। ये उद्योग पहली नजर में बेशक हानिकारक नहीं लगते पर यह एक खुला सच है कि अनजाने में ही इन 'गैर–हानिकारक' उद्योगों में अनेक परिवारों और मासूम बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है।

श्री संदीप कुमार ने कहा कि राजधानी में बच्चों से जुड़े अपराधों और अवेलहनाओं की शिकायतों पर कड़ाई से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अगर केंद्र सरकार बाल मजदूरी से जुड़े किसी भी कानून में संशोधन लाना चाहती है तो उसे ऐसे किसी संशोधन से पूर्व आम नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और इस क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से भी सुझाव लिए जाने चाहिए। ऐसा होने पर ही हम वास्तविकता में स्वराज की ओर बढ़ पायेंगे।

उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान किया है और आज इन अधिकारों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हरसंभव प्रयास करके इस अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर उजागर तथ्यों का प्रयोग करके राजधानी में बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करेगी। ■

गतिविधियां

घरेलू कामगारों की समस्या के समाधान के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष श्रीमती वन्दना कुमारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन

- **घरेलू कामगारों की न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ, प्लेसमेंट एजेंसियों के शोषण से मुक्ति एवं आश्रयगृह पर कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी**

दिल्ली सरकार ने घरेलू कामगारों की समस्या के समाधान के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष श्रीमती बन्दना कुमारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। यह बात दिल्ली के श्रम मंत्री श्री गोपाल राय ने ''विश्व घरेलू मजदूर दिवस'' के अवसर पर नेशनल प्लेटफोर्म फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स–दिल्ली यूनिट द्वारा आयोजित घरेलू कामगारों के सम्मेलन में कही है। इस समिति में श्रम विभाग के संसदीय सचिव श्री नरेश यादव, श्री कृष्ण कुमार एवं नेशनल प्लेटफोर्म फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स–दिल्ली यूनिट के प्रतिनिधि एवं श्रम विभाग के अधिकारी होंगे।

श्री राय ने बताया कि कमेटी घरेलू कामगारों की न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ, प्लेसमेंट एजेंसियों के शोषण से मुक्ति एवं आश्रयगृह के विषयों पर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार घरेलू कामगारों की सहायता के लिए सभी तरह के कदम उठाएगी। श्री राय ने कहा कि देश में लाखों घरेलू कामगार स्त्रियों के श्रम को पूरी तरह से अनदेखा किया जाता है। इसी तरह, हमारी अर्थव्यवस्था के भीतर घरेलू काम और उनमें सहायक के तौर पर लगे लोगों के काम को बेनाम और न दिखाई पड़ने वाले, गैर उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है.

दिल्ली के श्रम मंत्री ने कहा कि घरेलू कामगारों के लिए जल्द ही सरकार नए कानूनों का प्रावधान करेगी, जिससे उनको न्यूनतम मजदूरी, साप्ताहिक छुटटी, सामाजिक सुरक्षा एवं उनके स्वास्थ्य लाभ की सुविधा के साथ ही प्लेसमेंट एजेंसियों के शोषण से मुक्ति मिल सके।

साहित्य कला परिषद् ने किया नटखट उत्सव का आयोजन

साहित्य कला परिषद् की ओर से आयोजित नटखट उत्सव, बाल चित्रकला एवं शिल्प कला प्रदर्शनी का उद्घाटन दिल्ली सरकार के पर्यटन, कला एवं संस्कृति, मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने किया। इस अवसर पर श्री कपिल मिश्रा ने सभी प्रतिभागी बच्चों एवं उनके अभिभावकों को उनके प्रयास के लिए बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने के लिए निरन्तर प्रेरित करने की बात कही। उन्होंने

बच्चों की बनाई गई कलाकृतियों का अवलोकन करते हुए उनके कार्य की भरपूर प्रशंसा की और प्रदर्शनी में उपस्थित बच्चों से उनके अनुभव भी जाने। इस वर्ष साहित्य कला परिषद् से संगीत, नृत्य, नाटक एवं ललित कला, शिल्प कला की ग्रीष्मकालीन बाल कार्यशालाओं का आयोजन दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रो में 45 सरकारी स्कूलों में किया है। जिनमें 10 केन्द्र पर नृत्य, 10 केन्द्र पर संगीत, 10 केन्द्र पर नाटक, 10 केन्द्र पर ललित कला, 5 केन्द्र पर शिल्पकला की कार्यशालाऐं आयोजित की। ये कार्यशालाऐ परिषद् की भागीदारी योजना के अर्न्तगत शिक्षा निदेशालय के सहयोग से दिल्ली के विभिन्न स्कूलो में आयोजित की गई।

दिल्ली के मुख्य सचिव एक बैठक में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान राज्य के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुरूप दिल्ली में बढते प्रदूषण के कम करने के प्रयासों के तहत दिल्ली के मुख्य सचिव श्री के.के. शर्मा की अध्यक्षता में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में दिल्ली के पड़ोसी राज्यों से आने वाले भारी वाहनों के कारण बढते प्रदूषण और वाहनों को दिल्ली के प्रवेश द्वार पर ही रोक देने पर चर्चा हुई।

इस बैठक में हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेष के लोकनिर्माण विभाग के विषिष्ट सचिव, राजस्थान के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दिल्ली यातायात पुलिस के संयुक्त आयुक्त उपस्थित थे। इनके अतिरिक्त दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (वित), प्रधान सचिव(लोकनिर्माण विभाग), सचिव (पर्यावरण), सचिव–कम–आयुक्त (परिवहन) प्रधान मुख्य अभियंता (लोकनिर्माण) एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और भाषा मंत्री ने उर्दू अकादमी के सदस्यों से की मुलाकात

दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष और सदस्यों से दिल्ली सचिवालय में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मुलाकात के दौरान सभी सदस्यों को रमजान की मुबारकबाद दी।

उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष ने उर्दू अकादमी के कार्यप्रण ाली से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि उर्दू अकादमी उर्दू के विकास के लिए बहुत कम दरों पर किताबों का प्रकाशन कर रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री को उर्दू भाषा के हालात और दिल्ली में उर्दू शिक्षकों की कमी के बारे में बताया गया।

मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे इस मामले पर पूरा विचार

करेंगे और उर्दू भाषा के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। श्री केजरीवाल ने कहा कि उर्दू बहुत ही खूबसूरत भाषा है और इसके विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा के विकास के लिए सरकार उर्दू अकादमी के साथ है।

इस अवसर पर कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने कहा कि उर्दू अकादमी का कार्य प्रशंसनीय है और इसके विकास के हर संभव प्रयास किया जाएगा।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के क्रियान्वयन के लिए हुई बैठक

दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री श्री गोपाल राय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को, जिसमें 10 साल से पुराने डीजल के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है, क्रियान्वित करने हेतु एक ''संयुक्त क्रियान्वयन नीति'' बनाने के लिए हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त श्री चन्दर प्रकाश एवं श्री के. रविन्द्र नायक के साथ बैठक की।

श्री गोपाल राय ने दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास की बात कही। इस बैठक दिल्ली की परिवहन आयुक्त श्रीमती गीतांजली गुप्ता सहित विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। दिल्ली में पड़ोसी राज्यों, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में डीजल वाहनों का आवागमन होता है इसलिए इन राज्यों की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को क्रियान्वित करने में अहम भूमिका है।

श्री राय जी ने बताया कि वे शीघ्र ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा के परिवहन मंत्री के साथ श्री नीतिन गडकरी, परिवहन मंत्री भारत सरकार के साथ बैठक करेंगे।

श्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर 15 अप्रैल से 'ओवर लोडेड' वाहनों के विरूद्व उचित कार्रवाई होगी।

भारत में अमेरिकी राजदूत श्री रिचर्ड वर्मा, श्री अरविन्द केजरीवाल से मिले

भारत में अमेरिकी राजदूत श्री रिचर्ड वर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से भेंट की। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया भी उपस्थित थे। श्री केजरीवाल ने श्री रिचर्ड वर्मा से कई मामलों पर उनके सुझाव मांगे।

श्री रिचर्ड ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा चुनावों में प्रचण्ड जीत के लिए बधाई दी। श्री रिचर्ड ने अमेरिकी दूतावास की ओर पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों पर भी चर्चा की।

श्री केजरीवाल ने अन्य मामलों जैसे ठोस कचरा प्रबंधन, प्रदूषण रहित ऊर्जा, परिवहन, जल शोधन, नदी सफाई और प्रदूषण पर भी उनके सुझाव मांगे। श्री केजरीवाल ने कहा कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी या मौका है जब शहर को बदला जा सकता है, हम दिल्ली को सबसे अच्छा शहर बनाने के लिए प्रयासरत हैं और इसके लिए जनता की भागीदारी और उनके अमूल्य सुझावों की आवश्यकता है। हमे ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हें इन क्षेत्रों में कार्य का अनुभव है। श्री रिचर्ड ने भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा विषय पर भी श्री केजरीवाल और श्री सिसोदिया से चर्चा की। ■

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ 2015-16

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

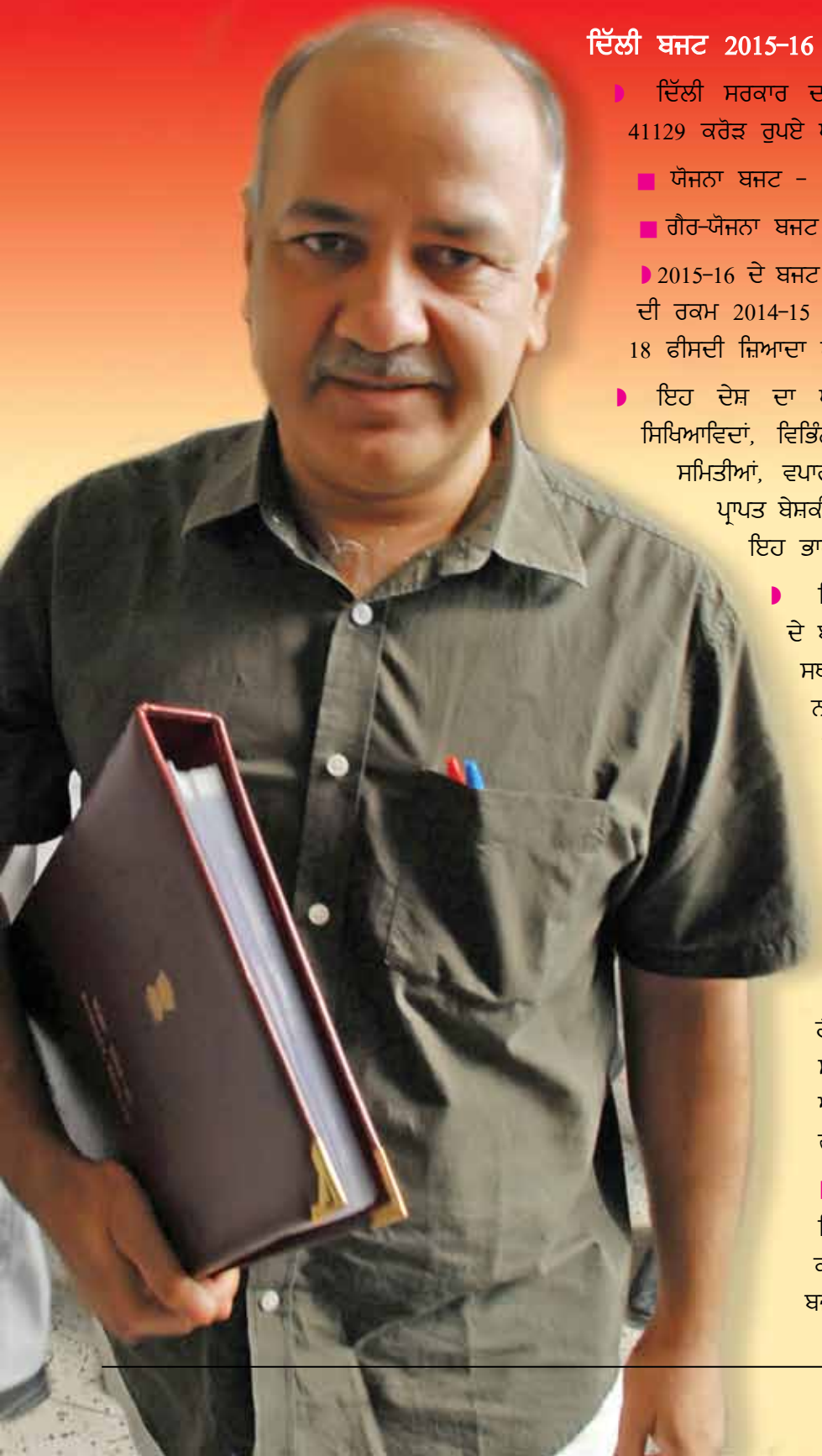

ਦਿੱਲੀ ਬਜਟ 2015-16 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਲਈ ਕੁਲ ਅਨੁਮਾਨ 41129 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।
  - ਯੋਜਨਾ ਬਜਟ - 19000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ
  - ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾ ਬਜਟ - 22129 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ
- 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਲਈ ਕੁਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 41,129 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 2014-15 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 34,790 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਰਾਜ ਬਜਟ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਿਖਿਆਵਿਦਾਂ, ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, RWAs, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਿਤੀਆਂ, ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀਪੂਰਨ ਬਜਟ ਹੈ।
- ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 253 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ''ਸਵਰਾਜ ਨਿਧੀ'' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
- ਹਰੇਕ ਰਾਜਸਵ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਡੀਯੂਡੀਏ) ਦਾ ਨਾਮ ਇਕ ਨਵੀਂ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਰਾਜ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਇਆਂ ਨੂੰ 2015-16 ਵਿਚ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਲ 5,908 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ 14.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਵਖ-ਵਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਡਿਸਿਟ੍ਰਕਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੇ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 1690 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- 2015-16 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਤੱਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਿਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਤਕ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਜਲਦ ਹੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪਹਿਲ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਰੋਧਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸੈਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

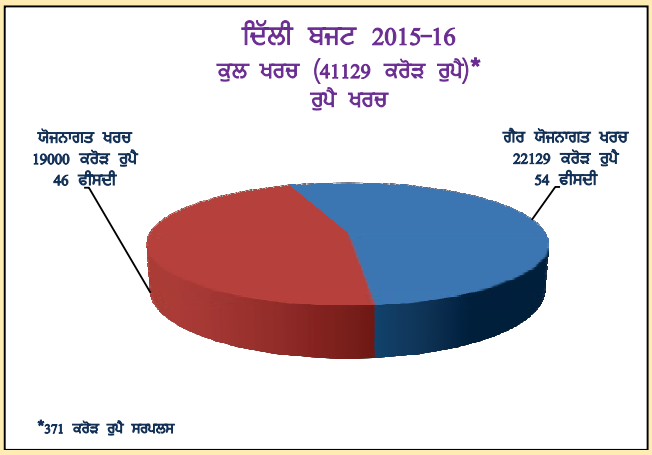

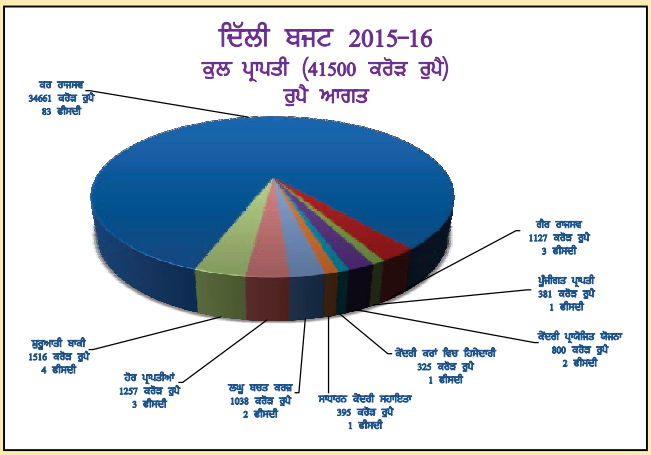

- ਸਿਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। 2015-16 ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ 4570 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2219 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ 106 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 1011 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
- ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਦਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 236 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 20,000 ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇਟਰਲ ਜਾਂ ਮਾਰਜਿਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 10 ਲਖ ਰੁਪੈ ਤਕ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
- ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਆਮ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇ ਐਂਡ ਪਲੇ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੇਡੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ੁਲਕ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਡ ਪਰਿਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਸਾਇਕ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀ/ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਵਸਾਇਕ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 310 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ।
- 10+2 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
- ਹਰੇਕ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਵਿਚ 100 ਸੀਟਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
- ਰਨਹੌਲਾ, ਛਤਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਕਰਵਾਲਾ ਵਿਚ 3 ਨਵੇਂ ਆਈਟੀਆਈ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 5 ਨਵੇਂ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸੰਸਥਾਨ - ਉਤਰੀ, ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ,ਮਧ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
- ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਉਨਤੀਕਰਨ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 12000 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਨ-ਕਯੂਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਨਾਂਗਲੋਈ, ਸਿਰਸਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਦੀਪੁਰ ਵਿਚ ਕੁਲ 1800 ਬਿਸਤਰ ਸਮਰਥਾ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
- 11 ਮੌਜੂਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਨਤੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 4000 ਨਵੇਂ ਬਿਸਤਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।

- ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿਤ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 500 ''ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ'' ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਰੀ, ਦੱਖਣੀ, ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਮਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖੋਹਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਨਾਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਟ੍ਰਾਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈਸੀਯੂ ਅਤੇ ਓਟੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 100 ਟ੍ਰਾਮਾ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ 42 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਬਿਸਤਰੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਿਹਤ ਆਂਕੜੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਸਰਕਾਰ 2016 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਡੀਟੀਸੀ ਦੇ ਲਏ 1380 ਸੇਮੀ-ਲੋ-ਫਲੋਰ ਬਸਾਂ, 500 ਮਿੰਨੀ ਬਸਾਂ ਖਰੀਦੇਗੀ ਅਤੇ ਕਲਸਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1000 ਨਵੀਂਆਂ ਬਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ।
- ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਵਜਨਿਕ-ਨਿਜੀ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਲਸਟਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਖ-ਵਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 10,000 ਬਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
- ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 5500 ਨਵੇਂ ਆਟੋ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਕਰੀਬ 1200 ਨਵੇਂ ਬਸ ਕਯੂ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
- ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ 64 ਮੈਟਰੋ ਫੀਡਰ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 304 ਨਵੀਂਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
- ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤਕ ਯਾਤਾਯਾਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ 15,000 ਰੁਪੈ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਪੀਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਸਾਰੇ ਡੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਕਲਸਟਰ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਕਲਸਟਰ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਡਰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ ਸਾਰਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 6 ਹੋਸਟਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

- ਸਰਕਾਰ ਸਲਮ ਅਤੇ ਝੁਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੇਕਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 300 ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਦਨ
- (ਕਰੇਚ) ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਚਾਲੂ ਵਿਤ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੇਜ-1 ਵਿਚ ਕਾਂਤੀਨਗਰ, ਚਿਤਰੰਜਨ ਪਾਰਕ, ਰੋਹਿਣੀ, ਪੱਛਮ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਛਤਰਪੁਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਲਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ, ਦਿਲੀ ਹੋਮਗਾਰਡ, ਦਿੱਲੀ ਸਿਵਿਲ ਡਿਫੇਂਸ ਕਾਰਮਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਿਦਾਨ

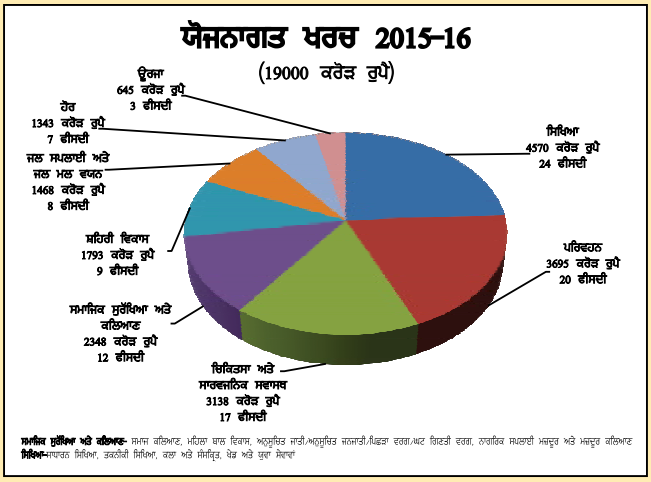

ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 20,000 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟੋ ਘਟ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਕਲਿਆਣ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਰਾਦਤ ਨਗਰ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਜਲ ਸ਼ੋਧਨ ਸੰਯੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਾਵਲ ਅਤੇ ਵਜੀਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਜਲ ਸ਼ੋਧਨ ਸੰਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਮੀਨਦੋਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ''ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ'' ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਸਤਤ ਅਤੇ ਕਰੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਖ ਸਕਣ। 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿਚ ਜੀਪੀਐਸ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸੇਂਸਰਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੈਬ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ''ਜਨ ਜਲ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ'' ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੁਦਾਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

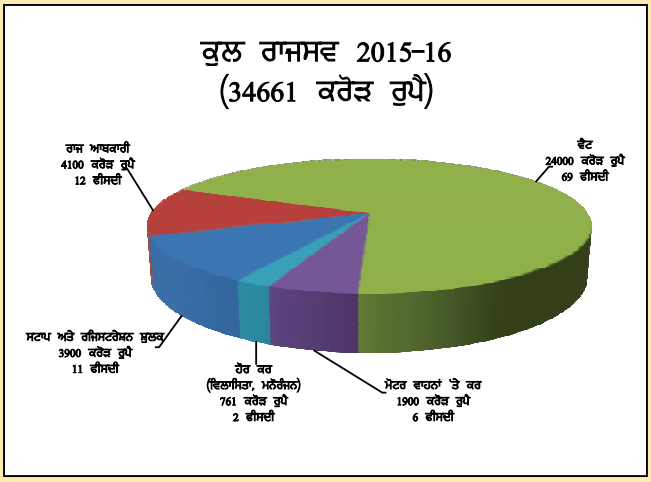

- ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ''ਖੁਦ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਲ ਸਿਰਜਨ'' ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਵਿਖ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
- ਦੇ ਲਈ ਜੀਐਸਡੀਐਲ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਚਿਤਰ ਆਂਕੜੇ ਰਾਜਸਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ,
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਤਿਕ੍ਰਮਨ /ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਮੁਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

- ਚਾਲੂ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਊਰਜਾ ਸੰਰਖਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸਮਰਥ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 12 ਲਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਰਿਆਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਵਹਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸੰਭਵਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਵ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ।
- ਇਕ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਕਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰਿਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲਕਸ਼ ਸੀ। ਕਰ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਗੌਣ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਵੈਟ ਰਾਜਸਵ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 24000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਲ ਰਾਜਸਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ ਦਾ 69 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
- ਲਕੜ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਗਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੈਟ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਕੂ-ਛੁਰੀ ਆਦਿ
- ਕਟਲਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਕਰ ਦੀ ਦਰ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੂਕਰਾਂ/ਕੜਾਹੀਆਂ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
- ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਮ ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਮ (ਵੈਕਸ) 'ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ 5 ਫੀਸਦੀ, 12.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ
- ਮੋਮ ਦੀ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
- ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪਰਿਵਹਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡੀਜਲ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਸਾਇਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ 100 ਤੋਂ 1500/- ਰੁਪੈ ਦੇ ਸ਼ੁਲਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵੇਸ਼ੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਆਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪਰਿਵਹਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵੇ-ਇਨ-ਮੋਸ਼ਨ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

- ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸ਼ੁਲਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਹਨ ਪਰਮਿਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਯਾਤ ਪਰਮਿਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਲਾਈਸੈਂਸ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਮੀਡੀਅਮ ਲਿਕਰ ਦੇ ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
- ਵਿਭਿੰਨ ਆਬਕਾਰੀ ਲਾਈਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਲਾਸਿਤਾ ਕਰ ਦੀ ਦਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ, ਕੇਬਲ ਟੀ.ਵੀ./ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ. ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 20 ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਰੁਪੈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
- ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਨਿਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰਾਂ ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਭਾਰਤੀਯ ਸਟੈਂਪ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬਧ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ, 5 ਰੁਪੈ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ 10 ਗੁਣਾ ਤਕ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 53 ਲਖ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜਸਵ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
- ਐਸੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਖੇਤੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਅਲਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸਵ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਤੋਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ■

ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ

ਆਟੋ ਸੰਵਾਦ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਲੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰਿਵਹਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਆਟੋ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਾਈਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਆਪਦੇ ਆਟੋ ਤੇ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਈਨੇਜ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਗੁਜਰੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਉਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਟੋ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ।

ਐਸੇ 4 ਵੈਂਡਰਾਂ ਜੋ ਜੀਪੀਐਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 10,000 ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਘਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਸੂਚੀ ਡਿਮਟ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਮਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਮਟ ਨੇ ਜੀਪੀਐਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9311900800 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ 'ਹੇਲਟ ਐਂਡ ਗੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਆਪਣਾ ਆਟੋ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਲੋਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਯਾਤਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰ. 42400400 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ/ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ/ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦਿੱਲੀ ਸਵੈਰੋਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ/ ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ/ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲਖ ਰੁਪੈ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ■

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਸਭਾਗਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਅਤੇ ਉਚੇ ਤੋਂ ਉਚੇ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

1031

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1031 ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਓ। ਐਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਗੁਪਤ ਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 67 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਮ ਕਮਾ ਕੇ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 5 ਟਾਪ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਤਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਬਰੋਕਾ ਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਕਤਰ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਸ੍ਰੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ■

ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 67 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਮ ਕਮਾ ਕੇ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 5 ਟਾਪ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ

ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵੰਦਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

- ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਗਾਰਾਂ ਦੀ ਘਟੋ ਘਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਲਾਭ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਆਸਰਾਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵੰਦਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ''ਵਿਸ਼ਵ ਘਰੇਲੂ ਮਜਦੂਰ ਦਿਵਸ'' ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਾਰ ਡੋਮੇਸਿਟਕ ਵਰਕਰਸ-ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਾਰ ਡੋਮੇਸਿਟਕ ਵਰਕਰਸ-ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਗਾਰਾਂ ਦੀ ਘਟੋ ਘਟ ਮਜਦੂਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਲਾਭ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏ ਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਆਸਰਾਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ;ਪਿਵਸ ਦਖਾ ਜਹਿੋਆਨੂੰ ਚਤ ਦਿਸਾ ਚੜ੍ਹਾੜ ਠਵ;ਰ ਦਾ ਡਾਸਾਤਵਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਗਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਪੈਣ ਵਾਲੇ, ਗੈਰ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਗਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟੋ ਘਟ ਮਜਦੂਰੀ, ਸਪਤਾਹਿਕ ਛੁੱਟੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਾਹਿਤਯ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਟਖਟ ਉਤਸਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਸਾਹਿਤਯ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਨਟਖਟ ਉਤਸਵ, ਬਾਲ ਚਿਤਰਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ

ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਹਿਤਯ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ, ਡਾਂਸ, ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਕਲਾ, ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾ ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਦਿਤੀ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 45 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਡਾਂਸ, 10 ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗੀਤ, 10 ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਨਾਟਕ, 10 ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਲਲਿਤ ਕਲਾ, 5 ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਲਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਿਆ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਯ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈਆਂ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕਤਰ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਘਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਉਚ ਪਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਵਾਰ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕਤਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਕਤਰ, ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਪਰਿਵਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕਤਰ (ਵਿਤ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕਤਰ (ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ), ਸਕਤਰ (ਪਰਿਆਵਰਣ), ਸਕਤਰ-ਕਮ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪਰਿਵਹਨ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਲੋਕਨਿਰਮਾਣ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਸਥਿਤ ਸਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਰਦੂ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕਲਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉਰਦੂ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਕਤਰੇਤ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਮਜਾਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਤੀ।

ਉਰਦੂ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਰਦੂ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਰਦੂ ਅਕਾਦਮੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਟ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਰਦੂ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਲਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਨੀਯ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਬੈਠਕ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ''ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੀਤੀ'' ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਰਿਵਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡੀਜਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 'ਓਵਰ ਲੋਡਿਡ' ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸ੍ਰੀ ਰਿਚਰਡ ਵਰਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸ੍ਰੀ ਰਿਚਰਡ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਿਚਰਡ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ।

ਸ੍ਰੀ ਰਿਚਰਡ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਿਤ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਿਚਰਡ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਲੋਂ ਪਰਿਆਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰਹਿਤ ਊਰਜਾ, ਪਰਿਆਵਰਣ, ਜਲ ਸ਼ੋਧਨ, ਨਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਂਦਾਰੀ ਦਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮੁਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਿਚਰਡ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ■

نے کہا کہ اردو بہت خوبصورت زبان ہے اور اس کی ترقی کیلئے زیادہ سے زیادہ کوشش کی جانی چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ اردو زبان کی ترقی کیلئے سرکار اردو اکادمی کے ساتھ ہے۔

اس موقع پر کلا، سنسکرتی ولسانی وزیر جناب کپل مشرا نے کہا کہ اردو اکادمی کا کام قابل تعریف ہے۔ اور اس کی ترقی کی ہر ممکن کوشش کی جائیگی۔

نیشنل گرین ٹریبیونل کے ہدایت کے کام کے متعلق کیلئے ہوئی میٹنگ

حکومت دہلی کے وزیر ٹرانسپورٹ جناب گوپال رائے نے نیشنل گرین ٹریبیونل کے ہدایت کو، جس میں 10 سال سے پرانے ڈیزل کے گاڑیوں پر پابندی لگانے کی بات کہی گئی ہے، کام کرنے سے متعلق کرنے کے ذریعہ ایک ''سینویوکت کریان وین نیتی'' بنانے کیلئے ہریانہ واتر پردیش کے ٹرانسپورٹ کمشنر جناب چندر پرکاش وجناب کے رویندر نائک کے ساتھ میٹنگ کی۔

جناب گوپال رائے دہلی میں ہوا کی عمدگی بڑھانے کیلئے ہر ممکن کوشش کی بات کہی۔ اس میٹنگ میں دہلی کے ٹرانسپورٹ کمشنر محترمہ گیتا نجلی گپتا سمیت محکمہ کے افسران بھی موجود تھے۔ دہلی میں پڑوسی ریاستوں، ہریانہ واتر پردیش سے بڑی تعداد میں ڈیزل گاڑیوں کی آمد ورفت ہوتی ہے اسلئے ان ریاستوں کی نیشنل گرین ٹریبیونل کے ہدایت کو پورا کرنے میں اہم رول ہے۔

جناب رائے جی نے بتایا کہ وہ جلد ہی اتر پردیش اور ہریانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ کے ساتھ جناب نتن گڈکری، وزیر مملکت برائے ٹرانسپورٹ بھارت سرکار کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔

جناب گوپال رائے نے کہا کہ سرکار نے یہ فیصلہ لیا کہ گرین ٹریبیونل کے ہدایتوں کو بہتر ڈھنگ سے کام کرنے کیلئے ہریانہ اور اتر پردیش کے محکمہ ٹرانسپورٹ کے افسران کے ساتھ ملکر 15 اپریل سے اوورلوڈیڈ گاڑیوں کے متعلق مناسب کارروائی ہوگی -

بھارت نے امریکی سفیر جناب رچرڈ ورما، جناب اروند کیجریوال سے ملے

بھارت میں امریکی سفارت کار جناب رچرڈ ورما نے دہلی کے وزیر اعلیٰ جناب اروند کیجریوال سے ملاقات کی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ جناب منیش سسودیا بھی موجود تھی۔ جناب کیجریوال نے جناب رچرڈ ورما سے کئی معاملوں پر ان سے تجویز مانگی۔

جناب رچرڈ ورما نے دہلی کے وزیر اعلیٰ جناب اروند کیجریوال کو دہلی اسمبلی انتخابات میں بھاری اکثریت جیت کے لئے مبارکبادی۔ جناب رچرڈ نے امریکی سفارت خانہ کی جانب ماحولیات اور سماجک خطہ میں کئے جارہے کاموں پر گفتگو کی۔

جناب کیجریوال نے دیگر معاملوں جیسے ٹھوس کچڑا پربندھن، آلودگی سے پاک بجلی، ٹرانسپورٹ، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، ندی صفائی اور آلودگی پر بھی ان سے تجویز مانگی۔ جناب کیجریوال نے کہا کہ یہ ایک بڑی ذمہ داری یا موقع ہے جب شہر بدلا جاسکتا ہے، ہم دہلی کو سب سے اچھا شہر بنانے کیلئے عہد پابند ہیں اور اس کیلئے عوام کی بھاگیداری اور ان کے قیمتی مشوروں کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جنہیں ان علاقوں میں کام کا تجربہ ہے۔ جناب رچرڈ نے بدعنوانی اور خواتین تحفظ سے متعلق پر بھی جناب کیجریوال اور سسودیا سے گفتگو کی۔ ■

ہوئے ان کے کام کی بھرپور تعریف کی اور نمائش میں موجود بچوں سے ان کے تجربہ بھی جانے۔اس سال ساہتیہ کلا پریشد سے سنگیت، رقص، ناٹک و للت کلا، شلپ کلا کی موسم گرما میں بچوں کے ورکشاپوں کا انعقاد دہلی کے مختلف علاقوں میں 45 سرکار اسکولوں میں کیا ہے۔جس میں 10 جگہوں پر رقص، 10 جگہوں پر سنگیت، 10 جگہوں پر ناٹک، 10 جگہوں پر للت کلا، 5 جگہوں پر شلپ کلا کی ورکشاپوں کا انعقاد کیا۔یہ ورکشاپ پریشد کی بھاگیداری منصوبہ کے تحت ڈائرکٹوریٹ برائے ایجوکیشن کے تعاون کے دہلی کے مختلف اسکولوں میں منعقد کیا گیا۔

دھلی کے چیف سیکریٹری ایک میٹنگ میں دھلی، اترپردیش، ھریانہ، اور راجستھان ریاست کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کرتے ھوئے

نیشنل گرین ٹریبیونل کے ہدایت کے مطابق دہلی میں بڑھتی آلودگی کے کم کرنے کی کوششوں کے تحت دہلی کے چیف سیکریٹری جناب کے کے شرما کی صدارت میں دہلی، ہریانہ، اترپردیش اور راجستھان کے نمائندوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد کی گئی۔اس میٹنگ میں دہلی کے پڑوسی ریاستوں سے آنے والے بھاری ٹرانسپورٹ کی وجہ سے بڑھتی آلودگی اور ٹرانسپورٹ کو دہلی میں داخل ہونے پر ہی روک دینے پر گفتگو ہوئی۔

اس میٹنگ میں ہریانہ کے اضافی چیف سیکریٹری اور ٹرانسپورٹ کمشنر، اترپردیش کے ٹرانسپورٹ کمشنر، اترپردیش کے لوک نرمان و بھاگ کے سینئر سیکریٹری، راجستھان کے اضافی ڈپٹی کمشنر نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا اور دہلی ٹریفک پولیس کے جنرل کمشنر، موجود تھے۔ان کے اضافی دہلی سرکار کے سینئر سیکریٹری (خزانہ)، سینئر سیکریٹری (لوک نرمان و بھاگ)، سیکریٹری (ماحولیات)، سیکریٹری کم کمشنر (ٹرانسپورٹ) چیف سینئر انجینئر (لوک نرمان و بھاگ) اور دیگر افیسران موجود تھے۔

دھلی کے وزیراعلیٰ اور وزیر لسانی نے اردو اکادمی کے وفد سے کی ملاقات

دہلی کے وزیراعلیٰ جناب اروند کیجریوال اور کلا، سنسکرتی و لسانی وزیر جناب کپل مشرا اردو اکادمی کے سیکریٹری اور ممبروں سے دلی سیکریٹریٹ میں ملاقات کی۔وزیراعلیٰ نے ملاقات کے دوران سبھی ممبروں کو رمضان کی مبارکبادی۔

اردو اکادمی کے سیکریٹری نے اردو اکادمی کے کامی نظام سے وزیراعلیٰ کو جانکاری دی۔انہوں نے بتایا کہ اردو کی ترقی کے لئے بہت کم شرح پر کتابوں کا شائع کر رہی ہے۔اس موقع پر وزیراعلیٰ کو اردو زبان کے حالات اور دہلی میں اردو اساتذہ کی کمی کے بارے میں بتایا۔

وزیراعلیٰ جناب اروند کیجریوال نے وفد کو بھروسہ دیا کہ اس معاملے پر پوری طرح غور کر کے اردو زبان کی ترقی کیلئے ممکن کوشش کریں گے۔ جناب اروند کیجریوال

سرگرمیاں

گھریلو کام کرنے والے کی وقت کے حل کیلئے ودھان سبھا نائب چیئر مین محترمہ وندنا کماری کی صدارت میں کمیٹی کی تشکیل۔

- گھریلو کام کرنے والے کی کم سے کم مزدوری سماجی تحفظ، بہتر صحت، پلیسمنٹ ایجنسیوں کے استحصال سے پاک اور آرام کرنے جگہ پر کمیٹی اپنی رپورٹ سرکار کو دے گی۔

دہلی سرکار نے گھریلو کام کرنے والے کے پریشانی کے حل کیلئے ودھان سبھا کے نائب صدر محترمہ وندنا کماری کی صدارت میں ایک کمیٹی تشکیل کیا ہے یہ بات دہلی کے وزیر محنت وروزگار جناب گوپال رائے نے ''عالمی گھریلو مزدور دیوس'' کے موقع پر نیشنل پلیٹ فورم فار ڈومسٹک ورکرس۔ دلّی یونٹ کے ذریعہ منعقد گھریلو کام کرنے والے کے سمیلن میں کہی ہے۔ اس سمیتی میں محکمہ محنت وروزگار کے پارلیمانی سیکریٹری جناب نریش یادو، جناب کرشن کمار اور نیشنل پلیٹ فورم فار ڈومسٹک ورکرس۔ دلّی یونٹ کے نمائندہ اور محکمہ محنت وروزگار کے آفیسران ہونگے۔

جناب رائے نے بتایا کہ کمیٹی گھریلو کام کرنے والے کی کم سے کم مزدوری، سماجی تحفظ، بہتر صحت، پلیسمنٹ ایجنسیوں کے استحصال سے پاک اور آرام کرنے کی جگہ کے متعلق اپنی رپورٹ سرکار کو دے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ کی بنیاد پر سرکار گھریلو کام کرنے والے کی مدد کیلئے سبھی طرح کے قدم اٹھائے گی۔ جناب رائے نے کہا ملک میں لاکھوں گھریلو کام کرنیوالی خواتین کے محنت کو پوری طرح سے ان دیکھا کیا جاتا ہے اس طرح ہماری اقتصادی حالت کے اندر گھریلو کام اور ان میں معاون کے طور لگے لوگوں کے کام کو بے نام اور نادکھائی پڑنے والے، غیر پیداوار کی فہرست میں رکھا جاتا ہے۔

دہلی کے وزیر محنت وروزگار نے کہا کہ گھریلو کام کرنے والے کیلئے جلد ہی سرکار نئے قانون کا تجویز کرے گی، جس سے ان کو کم سے کم مزدوری، ہفتہ وار چھٹی، سماجی تحفظ اور ان کے بہتر صحت کی سہولت کے ساتھ ہی پلیسمنٹ ایجنسیوں کے استحصال سے آزادی مل سکے۔

ساہتیہ کلا پریشد نے کیا نٹ کٹ اُتسو کا انعقاد

ساہتیہ کلا پریشد کی جانب سے نٹ کٹ اتسو، بال چتر کلا اور شلپ کلا نمائش کا افتتاح دہلی سرکار کے سیاح، سنسکرتی وثقافتی کے وزیر جناب کپل مشرا نے کیا۔ اس موقع پر جناب کپل مشرا نے سبھی حصہ لینے والے بچوں اور ان کے سرپرستوں کو ان کے کوشش کے لئے مبارکباد دی۔ اس موقع پر انہوں نے سرپرستوں سے بچوں انکی خواہش کے مطابق کام کرنے کیلئے حوصلہ آفزائی کرنے کی بات کہی۔ انہوں نے بچوں کی بنائی ہوئی فن پاروں کا معائنہ کرتے

1031

بدعنوانی مخالف ہیلپ لائن نمبر

پھر ویڈیو بنالیں۔انھوں نے کہا کہ ریکارڈنگ کرنے کے بعد بدعنوانی مخالف ہیلپ لائن نمبر 1031 پر اپنی شکایت درج کرائیں۔ایسے میں شکایت کرنے والے کی پہچان پوشیدہ رکھی جائے گی۔

جناب کیجریوال نے کہا کہ پچھلے سال 49 دن کی سرکار کا کام کاج دیکھ کر ہی دہلی کی عوام نے انہیں 67 سیٹیں دیکر بھاری اکثریت دیا ہے۔انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار، جھوٹے وعدے نہیں کرتی بلکہ اپنے وعدوں کو پورا کرتی ہے۔انہوں نے بتایا کہ بجلی کے پرانے بلوں کو ٹھیک کرنے کی تجویز بھی بنائی جارہی ہے۔انہوں نے یہ بھی کہا کہ پورے عالم میں بھارت کے لوگ نام کما کر اہم رول ادا کررہے ہیں لیکن اپنے ملک میں آکرنا کام ہوجاتے ہیں کیونکہ یہاں بدعنوانی ہے۔جناب اروند کیجریوال نے کہا کہ سرکار اگلے پانچ برسوں میں دہلی کو ملک کا پہلا بدعنوانی سے پاک ریاست بنانے کے ساتھ ساتھ دہلی کو دنیا کے 5 ٹاپ بدعنوانی سے پاک شہروں میں شامل کرادے گی۔

انہوں نے سبھی محکمہ کے صدروں کو ہدایت جاری کرکے کہا کہ وہ اپنے دفتروں میں لوگوں کو اپنے ساتھ موبائیل لانے کی اجازت دیں تاکہ لوگ رشوت مانگنے پر ریکارڈنگ کرسکیں۔انہوں نے افسران کو بھروسہ دلایا کہ اگر وہ ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے تو کوئی غلطی ہوجانے پر بھی وہ چٹان کی طرح ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے لیکن اگر بدعنوانی کریں گے تو آخر تک بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔انہوں نے کہا کہ دہلی کو بدعنوانی سے پاک ریاست بنانے کیلئے تکنیک کا استعمال ہوگا اور موجودہ قانون کو آسان بنایا جائے گا۔

اس موقع پر جناب نائب وزیراعلیٰ جناب منیش سسودیا، دہلی کے چیف سکریٹری جناب کے کے شرما، محکمہ انتظامیہ سدھار کے سکریٹری جناب ارون بروکا نے بھی موجود لوگوں کو خطاب کیا۔اس پروگرام کے آخر میں سکریٹری عوام رابطہ جناب سجن سنگھ یادو نے آخر میں سبھی کا شکریہ ادا کیا۔

جناب کیجریوال نے کہا کہ پچھلے سال 49دن کی سرکار کاکام کاج دیکھ کر ہی دہلی کی عوام نے انہیں 67سیٹیں دیکر بھاری اکثریت دیا ہے۔انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار ، جھوٹے وعدے نہیں کرتی بلکہ اپنے وعدوں کو پورا کرتی ہے۔انہوں نے بتایا کہ بجلی کے پرانے بلوں کو ٹھیک کرنے کی تجویز بھی بنائی جارہی ہے۔انہوں نے یہ بھی کہا کہ پورے عالم میں بھارت کے لوگ نام کماکر اہم رول ادا کررہے ہیں لیکن اپنے ملک میں آکرنا کام ہوجاتے ہیں کیونکہ یہاں بدعنوانی ہے ۔جناب اروندکیجریوال نے کہا کہ سرکار اگلے پانچ برسوں میں دہلی کو ملک کا پہلا بدعنوانی سے پاک ریاست بنانے کے ساتھ ساتھ دہلی کو دنیا کے 5ٹاپ بدعنوانی سے پاک شہروں میں شامل کرادے گی۔

دھلی کے وزیراعلیٰ نے شروع کی

بدعنوانی مخالف ھلپ لائن

دھلی کے وزیراعلیٰ جناب اروند کیجر یوال نے ٹالکٹورہ اسٹیڈیم میں منعقدہ ایک شاندار پروگرام میں بدعنوانی مخالف ہیلپ لائن شروع کی ۔اس موقع پر انھوں نے دہلی سے بدعنوانی پوری طرح مٹانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اگلے پانچ برس میں دہلی کو ملک کا پہلا بدعنوانی سے پاک ریاست بنادیا جائیگا۔

انھوں نے کہا کہ بدعنوانی بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔اوراونچے سے اونچے رتبہ پر بیٹھا فرد بھی بدعنوانی میں ملوث ہوگا تو اسے جیل بھیجا جائے گا۔

انھوں نے دہلی کی عوام سے ایک بار پھر اپیل کی اگر ان سے کوئی رشوت مانگتا ہے تو منع نہ کریں اور رشوت مانگنے والی کی آواز ریکارڈ کرلیں یا

کو بھی چالان سے بھی نجات ملی گی اس کے تحت رات میں اپنے گھر جا رہے آٹو ڈرائیور اپنے آٹو پر ایک ڈیجیٹل سائنج بورڈ لگائے گا جس میں اس راستے کا ذکر ہوگا جس سے وہ آٹو ڈرائیور گزرے گا اس سے کسی بھی آٹو ڈرائیور پر یہ کہہ کر کہ اس نے جانے سے انکار کر دیا اس پر جرمانہ نہیں کیا جا سکے گا۔ اور مسافروں کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ آٹو کس راستے سے جائے گا۔

ایسے چار ونڈروں جو جی پی ایس لگانے کیلئے 10000 روپئے سے کم لے رہے ہیں کی فہرست تاریخ محکمہ کے ذریعہ محکمہ ٹرانسپورٹ کی سائٹ پر ڈال دی گئی ہے۔ محکمہ ڈمپٹ نے اس کا کارگر اشتہار بھی دیا گیا ہے۔ ڈمپٹ نے جی پی ایس ہلپ لائن نمبر 9311900800 جاری کیا ہے۔ جس پر جی پی ایس سے متعلق جانکاری لی جا سکتی ہے۔

راجدھانی میں مختلف جگہوں پر آٹو رکشا اسٹینڈ بنائے جا رہے ہیں۔ جہاں ''ہالٹ اینڈ گو نظام'' کے تحت آٹو رکشا ڈرائیور اپنا آٹو کھڑا کر سکے گا۔ اس کیلئے متعلقہ محکمہ کو ہدایت جاری کی گئی ہے اس اسٹینڈوں پر کھڑے ہونے پر کسی بھی آٹو ڈرائیور پر جرمانہ نہیں لگایا جا سکے گا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے جاری مسافر ہلپ لائن نمبر 42400400 پر موجود شکایتوں پر کی گئی کارروائی کی جانکاری مسافروں کو بھی دی جائے گی۔

اس موقع پر جناب سندیپ کمار نے کہا کہ دہلی سرکار کا ایس سی ایس ٹی / او بی / دیگر پچھڑا طبقہ / اقلیت اور معذور شخص وکاس نگم دہلی سوروزگار یوجنا کے تحت کمرشیل گاڑی خریدنے کیلئے ایس سی / ایس ٹی / او بی / دیگر پچھڑا طبقہ / اقلیت اور معذور طبقہ کے لوگوں کو پانچ لاکھ روپئے تک قرض مہیا کر رہا ہے۔ ■

ٹرانسپورٹ محکمہ نے انعقاد کیا

آٹو مکالمہ

دھلی کے وزیراعلیٰ جناب اروند کیجر یوال نے ٹرانسپورٹ محکمہ کی جانب سے دہلی ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے نزدیک براڑی میدان میں منعقد آٹو مکالمہ میں آٹو رکشا ڈرائیوروں کو خطاب کیا۔اس موقع پر وزیرٹرانسپورٹ جناب گوپال رائے ، وزیرخاندانی بہبود جناب سندیپ کمار،ایم ایل اے ،محکمہ ٹرانسپورٹ کے اعلیٰ آفیسران اور مختلف تنظیموں کے افراد موجود تھے۔

جناب اروند کیجر یوال نے بتایا کہ سرکار آٹو رکشا ڈرائیوروں کیلئے کئی رفاہی منصوبوں کو شروع کررہی ہے۔

وزیرٹرانسپورٹ جناب گوپال رائے نے بتایا محکمہ ٹرانسپورٹ نے کام سے گھر لوٹ رہے آٹو ڈرائیوروں کے لئے ایک سائیج نظام کی شروعات کی جس سے مسافروں کو سہولت کے ساتھ ساتھ آٹو ڈرائیوروں

- شراب پر آبکاری محصول آمدنی میں بھاری بدلاؤ کرتے ہوئے ٹرانسپورٹ پرمٹ سطح سے درآمد پرمٹ سطح پر لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آبکاری محصول میں بدلاؤ نہ کرتے ہوئے صرف لائسنس محصول میں بڑھوتری کی جارہی ہے۔
- دہلی میڈیم لکّر کے غیر مروج برانڈ کو سال کے دوران مرحلہ وار طریقے سے ہٹانے کی تجویز ہے۔
- مختلف آبکاری لائسنسوں کے تجدید کاری کے طریقہ کار میں سدھار کرتے ہوئے آسان بنایا جارہا ہے۔ جس سے اس تکنیکی میں لگانے والے وقت میں کٹوتی ہوگی۔
- سبھی جگہوں پر لاگو عیش وعشرت ٹیکس کی شرح 10 فیصد سے بڑھا کر 15 فیصد کی جائیگی۔
- تفریحی ٹیکس کیبل ٹی وی/ڈی ڈی ایچ خدمات پر 20 روپئے سے بڑھا کر 40 روپئے کرنے وسینما گھروں میں ٹیکٹوں پر 20 فیصد سے بڑھا کر 40 فیصد کرنے کی تجویز ہے۔
- کمپنیوں وبھاگیداری فرموں کے نام پر رجسٹریشن شدہ سبھی نجی ٹرانسپورٹ کے رجسٹریشن ٹیکس میں ودھان دروں پر 25 فیصد کی بڑھوتری کی جارہی ہے۔
- ہندوستانی اسٹامپ ایکٹ بدلاؤ کی تجویز ہے تاکہ جرمانے کی شرح تاخیر کے ہر ایک مہینے کیلئے کمی رقم کے 2 فیصد کی شرح سے دلیل کے ساتھ بنائی جائے موجودہ میں 5 روپئے سے اسٹامپ ڈیوٹی میں کمی کے مقدار کے 10 گنا تک، جرمانہ لگ سکتا ہے۔

قانون کے بااثر نافذ وقانونی نظر سے صاف ستھری بنانے کیلئے اس کے کچھ دیگر پراودھان میں ترمیم کیا جائے۔

- دہلی کے کھیتی کی زمین کی سرکل ریٹ موجودہ 53 لاکھ روپئے سے بڑھا کر مالی ضلع کے مطابق 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
- ایسی کھیتی کی زمین جن میں ڈی ڈی اے کی لینڈ پولنگ پالیسی لاگو ہے کھیتی کی زمین کی الگ درجہ ہوگی جس کی سرکل شرحوں میں مالیاتی ضلعوں کے مطابق 2.25 کروڑ روپئے سے 3.5 کروڑ روپئے کی حد تک بڑھوتری کی تجویز ہے

- چالو مالی سال کے دوران ایک بجلی مہیا کرنے والی پلانٹ کا قیام کیا جائے گا۔تا کہ اچھی بجلی پروجیکٹوں اور اسٹریٹ لائٹنگ دیگر کیلئے رقم کا انتظام کیا جا سکے۔
- ہوا کی خصوصیات میں سدھار کیلئے چالو مالی سال کے دوران سبھی متعلقہ سرکاری ایجنسیوں کے ذریعہ 12 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔
- قومی راجدھانی خطہ دہلی میں ماحولیات موافق گاڑی کو بڑھاوا دینے کیلئے بیٹری سے چلنے والے چار پہیئے دو پہیئے گاڑیوں کی نئی خرید کر دہلی سرکار سبسڈی عطا کرے گی۔جو مرکزی سرکار کے ذریعہ دی جانے والی سبسڈی کے علاوہ ہوگی۔
- ممکن ہے: بھارت کی تاریخ میں یہ پہلا بھاگیداری بجٹ ہے جس میں جن سادھارن بھاگیداری اخراجات یوجنا اور مالیات کو بڑھانا دونوں میں رہی۔
- ایک بہترین جگہ کی صورت میں دہلی کی شان بان کو دیکھتے ہوئے پربندھان میں صاف ستھری اور ٹھہراؤ کر پرشاسن میں مستقبل اور حال کو دھیان میں رکھا گیا ہے۔
- ٹیکس علاقہ کا دائرہ بڑھانے کیلئے ویپارک آسوچائیں ایکترت کرنا ہی مقصد تھا۔ٹیکس شرح میں بدلاؤ کو غیر اہم رکھا گیا ہے۔
- ویٹ مالیات کا نشانہ تقریباً 24000 کروڑ روپئے ہے۔تو سرکار کے کل مالیات تخمینہ نشانہ کا 69 فیصد ہے۔
- لکڑی وعمارتی سامان جو کہ بہترین گھر تعمیرات سامان ہے اس پر ویٹ 12.5 فیصد گھٹا کر 5 فیصد کر دیا گیا ہے۔چاقو، چھری، دیگر کلڑی چیزوں پر ٹیکس کی شرح 12.5 فیصد سے گھٹا کر 5 فیصد کرنی تجویز ہے۔پریسر کوکر، کڑھائیاں جیسے دیگر رسوئی کے برتنوں پر اتنا ہی ہے۔
- اب سبھی طرح کے موم پر ویٹ کی شرح 12.5 فیصد رہی گی ۔مستقبل میں مختلف طرح کے موم (ویکس) پر ترتیب وار: 5 فیصد ،12.5 فیصد اور 20 فیصد کی شرح سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔اس میں ویٹ شرحوں میں غیر واضح ختم ہو جائے گی۔
- عوامی ٹرانسپورٹ نظام کی بسوں ودہلی میں داخل ہونے والی ٹیکسوں کو چھوڑ کر ڈیزل سے چلنے والے امر خلاف پیشہ ٹرانسپورٹ پر 100 سے 1500 روپئے کے چنگی کی وصولی تا کہ دہلی میں داخل ہونے والی صاف ستھری ہوا میں سدھار کے لئے ماحولیات موافق ،عوامی ٹرانسپورٹ نظام، وانموشن پلوں کا قیام ودیگر تدبیر کئے جا سکیں۔

- دہلی سرکار نجی علاقے کی فعال بھاگیداری کیساتھ کام کرنے والی خواتین کیلئے 6 ہوسٹل بنانے کی منصوبہ بنا رہی ہے۔
- سرکار سلم اور جھگی جھونپڑی بستیوں میں بال وکاس پروگرام کے تحت 300 شیسو سدن (کیرچ) بہتر مہیا کرانے کی یوجنا بنا رہی ہے۔
- چالو مالی سال کے دوران فیز I میں کانتی نگر، چتر نجن پارک، روہنی، پچھم وہار اور چھتر پور نئے بزرگوں کے آرام کرنے کی جگہ کی تعمیری کام شروع کرنے کی تجویز ہے۔

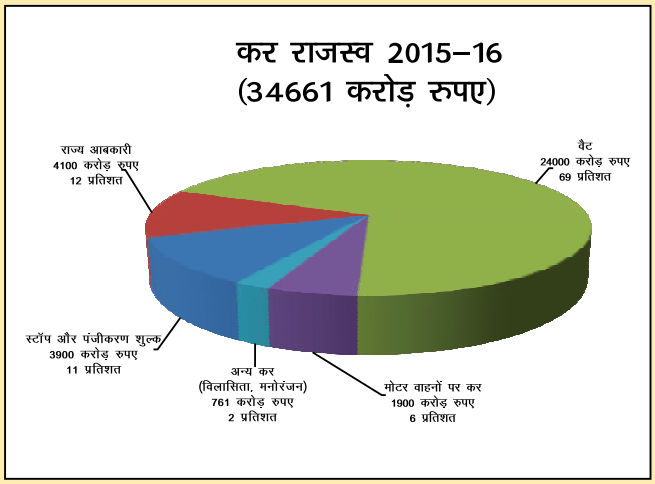

- دہلی سرکار نے ڈیوٹی کے وقت جان قربان کرنے والے حفاظتی سپاہیوں اور نیم فوجیوں کے جوانوں جو دہلی کے رہنے والے ہوں کے خاندان کو ایک کروڑ روپئے معاوضہ دینے کا فیصلہ کیا۔ دہلی پولیس، دہلی ہوم گارڈ، دہلی سول ڈیفنس ملازمین کے معاملے میں ڈیوٹی کے دوران جان دینے کی صورت میں صحیح معاوضہ کی رقم ادا کی جائے گی۔
- سرکار نے انتہائی نقصان اور خشک سالی سے فصل نقصان کی صورت میں 20000 روپئے فی ایکڑ کی شرح سے کسانوں کو عنایتی رقم دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
- نرمان شرمکوں اور ان کے خاندان کو کمترین ادھی سوچت مزدوری کی ادائیگی اور بہتر کلیان سہولت مہیا کرنے کیلئے شرمک وکاس میشن شروعات کی گئی ہے۔

- شہر میں پانی کی بڑھتی مانگ کو پورا کرنے کیلئے پانی کا ذخیرہ بڑھانے کے واسطے ارادت نگر نیا ٹرٹمنٹ پلانٹ قائم کیا جائے گا۔ اور چندراول اور وزیرآباد ٹرٹمنٹ پلانٹ کی تجدید کاری کی جائے گی۔
- واٹر ٹرینکروں پر عوامی نگرانی کیلئے ایک نیا پورٹل شروع کیا گیا ہے تاکہ لوگ واٹر ٹرینکروں پر سخت نظر اور کڑی نگرانی رکھ سکیں۔ 400 سو زیادہ ٹرینکروں میں جی پی ایس اور واٹر سینسرس لگائے گئے ہیں۔ اور ایک ویب ادھارت نظام کے ذریعہ ان کے آنے جانے پر سخت نگرانی رکھی جا رہی ہے۔

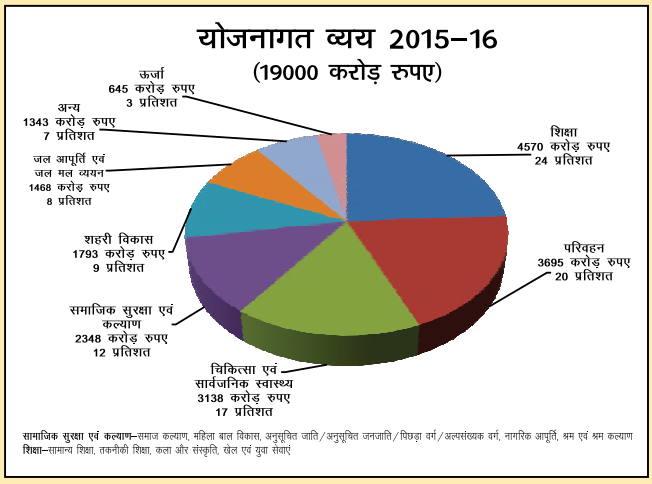

- 'جل جن پربندھک یوجنا' نام کا ایک نیا پروگرام شروع کیا جائے گا۔ جس کا مقصد پانی اور سیور کے سہولتوں کے انتظام میں بہتر ڈھنگ سے جماعت کو شامل کرنا ہے۔
- شہریوں کا اچھا اور خوبصورت ڈھنگ سے پانی اور سیور خدمات مہیا کرنے کیلئے ''میٹر ریڈنگ اور بل مہیا کرنے والے'' کیلئے ایک موبائیل ایپ شروع کیا جائے گا۔
- دہلی میں مستقبل میں غیر قانونی تعمیرات کو روکنے کیلئے جی ایس ڈی ایل نیمت انترال پر مصنوعی سیارہ نقشہ انکڑا محکمہ مالیات کو مہیا کرے گا۔ جن میں نئے قانونی رغیر قانونی تعمیرات واضح طور سے نشاندہی کی جائیں گی تاکہ انھیں روکنے کیلئے متعلقہ افیسر صحیح کارروائی کر سکیں۔

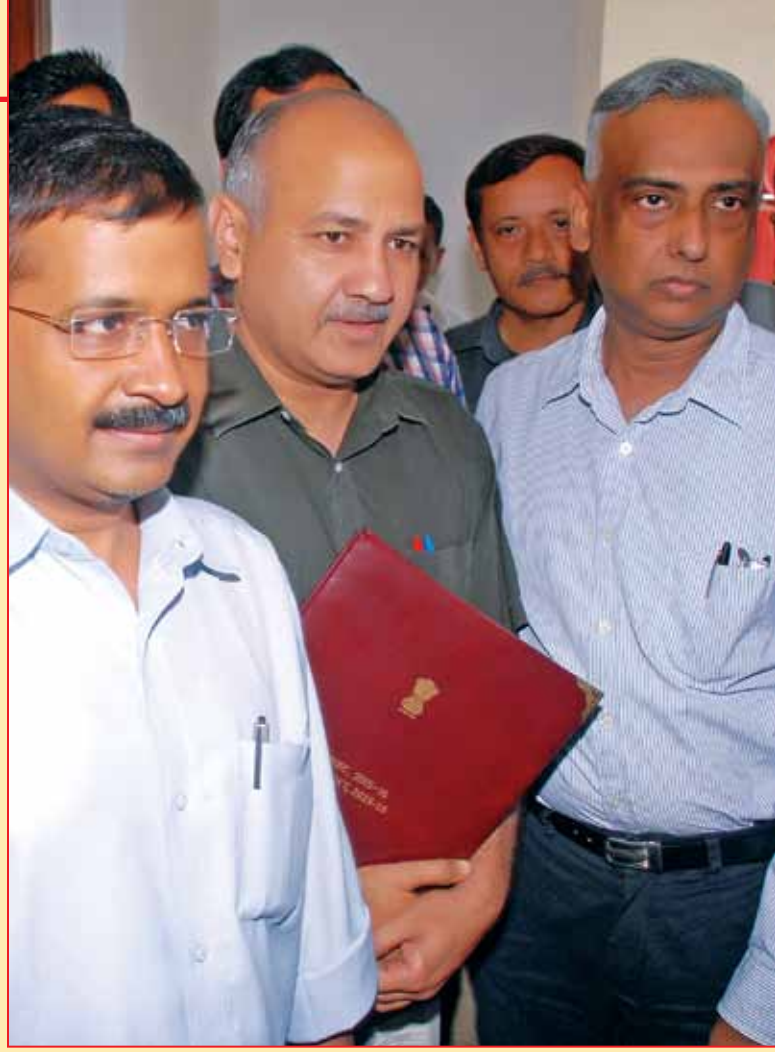

- 11 موجودہ اسپتالوں کو نیا روپ دینے اور ان کے ترقی کی یو جنا ہے۔جس سے اگلے دو برسوں میں ان اسپتالوں میں 4000 نئے بستر جوڑے جائیں گے۔
- سرکار چالو مالی سال کے دوران دہلی کے سبھی بھاگوں میں 500 ''محلّہ کلینک'' کھولنے کی یوجنا بنا رہی ہے۔
- محلّہ کلینک میں آنے والے مریضوں کو بہتر خدمات مہیا کرنے کے لئے شمالی، جنوبی، پوربی،، مغربی اور مرکزی دہلی میں جدید سہولتوں کے ساتھ 5 مرکزی ماتحت پریوک شالائیں کھولی جائیں گی۔
- سرکار کھیلوں کے دوران زخمی ہونے والے کھلاڑیوں کے صحت یابی کے لئے لوک نائک اسپتال میں ایک جدید ٹراما سینٹر کھولنے کی یوجنا بنا رہی ہے۔جس میں آئی سی یو اور او ٹی سہولت سمیت 100 ٹراما بستروں کا انتظام ہوگا۔
- معاشی طور سے پچھڑے طبقوں کے لئے 42 پرائیویٹ اسپتالوں میں مفت بستر مہیا کے لئے آن لائن بکنگ کی انتظام کیا جائے گا۔

- صحت آنکڑے درج کرنے اور دہلی سرکار کے ریکارڈ رکھنے کے لئے ہر ایک کو صحت کارڈ جاری کئے جائیں گے۔
- ٹرسٹ کلینکوں/ دواخانوں کے لئے جاری دہلی کے شہریوں کو مفت طبی علاج عطا کی جائے گی۔

سرکار 2016 کے آخر تک ڈی ٹی سی کے لئے 1380 سبھی لوفلور بسیں 500 منی بسیں خریدے گی اور کلسٹر اسکیم کے تحت لگ بھگ 1000 نئی بسیں شامل کرے گی۔

- مسافروں کی الگ الگ طرح کی ضرورت پوری کرنے کے لئے عمومی، نجی بھاگیداری کلسٹر یوجنا کے تحت نجی علاقہ سے مختلف خصوصیت والی 10000 بسیں شامل کرنے کی تجویز ہے۔
- این سی آر کے قریب 5500 نئے آٹو پرمٹ جاری کئے جا رہے ہیں۔
- قریب 1200 نئے بس کیوشیلٹرس بنانے کی تجویز ہے۔
- چالو برس میں 64 میٹرو فیڈر مارگوں پر قریب 304 نئی منی بسیں شامل کرنے کی تجویز ہے۔
- آخری دوری تک آمدورفت مہیا کرانے کے لئے سرکار دہلی میں ای رکشا کو نہایت امنگ کے ساتھ لا رہی ہے۔ای رکشا کی خرید پر 15000 روپے کی سبسڈی مہیا کی جائے گی۔
- دہلی سرکار نے ٹیکسیوں اور آٹو سمیت سبھی عوامی ٹرانسپورٹ کے لئے جی پی ایس نظام کو خاص کر دی ہے۔تاکہ ٹرانسپورٹ کی حالت کا پتہ لگایا جا سکے۔
- سبھی ڈی ٹی سی اور کلسٹر بسوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی تجویز ہے۔
- دہلی سرکار نے سبھی ڈی ٹی سی اور کلسٹر بسوں میں مارشل تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔تاکہ جرائم کا خطرہ کو ختم کیا جا سکے۔اور خواتین مسافروں کی دیکھ بھال اور حفاظت بہتر کی جا سکے۔
- صحیح فہرست اوقات مہیا کرانے کے لئے مسافر اطلاع نظام شروع کی جائے گی۔

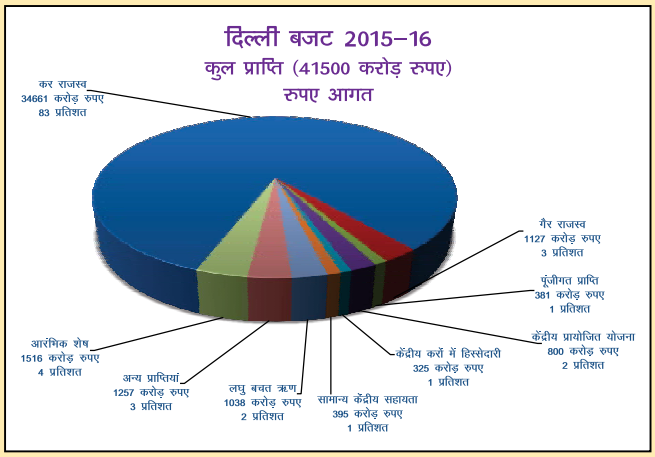

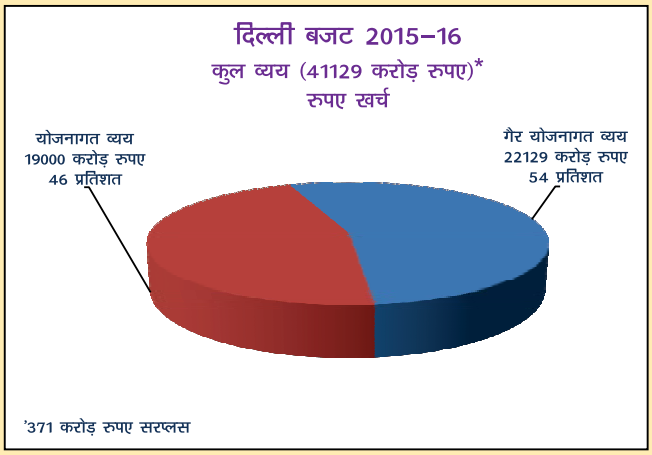

- عالمی تنظیموں اور دنیا کی دیگر سرکاروں سے حاصل گذارشوں میں ہم آہنگی کرنے کے لئے مالیہ اور یوجنا محکمہ کے متعلق ایک لابی بنایا جائے گا۔
- تعلیم سرکار کی پہلی فوقیت ہے۔ 2015-16 میں اس میدان کے لئے 4570 کروڑ روپے کا قرارداد منظور کئے گئے ہیں۔ یہ پچھلے سال کے 2219 کروڑ روپے کے عوض سے 106 فی صد زیادہ ہے۔ یہ ملک میں پہلا موقع ہے جب کسی سرکار نے تعلیم کے بجٹ میں دوگنا بڑھوتری کی ہے۔
- سرکار کی ایجنڈا میں سبھی 1011 سرکاری اسکولوں میں جدید سہولتیں اور بنیادی ڈھانچہ مہیا کرانا ہے۔
- جدید سہولتوں اور ڈھانچے کے ساتھ 50 اسکولوں کو ماڈل اسکول کے روپ میں ترقی یافتہ بنایا جائے گا۔ بہرکیف سبھی اسکول ماڈل اسکول بن جائیں گے۔ 236 نئے اسکول کھولنے کی منصوبہ ہے۔
- سرکاری اسکولوں کے اب تک 20000 باقاعدہ اساتذہ کی بھرتی کئے جانے کا امکان ہے۔ تاکہ طلباء اساتذہ تناسب میں سدھار لایا جاسکے۔
- اچھی تعلیم اور بہتر وکاس گارنٹی پروگرام شروع کیا جائے گا۔ جس میں طلباء بنا کسی کولیٹرل یا مارجن رقم کے 10 لاکھ روپے تک کے تعلیم قرض مہیا کرسکیں گے۔
- لڑکیوں کے لئے تعلیمی قرض پر بیاض کی درعام بیاض دروں سے کم ہوگی۔
- کھیل سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے کے لئے سرکار نے 'پے اینڈ پلے' اسکیم یعنی بھگتان کرو اور کھیلو پروگرام شروع کیا ہے۔ جس کے تحت عام آدمی معمولی قیمت ادا کر کے سرکاری کھیل پریسروں اور اسٹیڈیموں کی سہولتوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
- دہلی سرکار کی بہتر اور پختہ وکاس میں ڈگری/ڈپلوما پڑھنے والوں کے لئے اچھے کالج مہیا کرنے کی جانب میں کام کر رہی ہے۔ پروفیشنل تعلیم کو بڑھاوا دینے کے لئے 310 کروڑ روپے مقرر ہے۔
- 10+2 امتحان پاس کرنے کے بعد ہر ایک طلباء کو دو پرمان پتر ایک عام تعلیم اور دوسرا مہارت تعلیم کے لئے دینے کی منصوبہ ہے۔
- ہر ایک پولی ٹیکنیک میں 100 سیٹیں کرنے کا بھی منصوبہ ہے۔
- رنہولا، چھترپور، اور بکّر والا میں 3 نئے آئی ٹی آئی کھولنے کا منصوبہ ہے۔ 5 نئے پولی ٹیکنیک جگہوں، شمالی، شمال مشرقی، مرکزی، نئی دہلی اور مغربی ضلع میں ایک ایک کھولنے کا منصوبہ ہے۔
- نیتاجی سبھاش انڈسٹریل ایریا کی ترقی ایک یونیورسیٹی کے روپ میں کیا جائے گا۔ جس سے 5 سال کی وقفہ میں اس مقام میں طلباء کی تعداد بڑھا کر 12000 کی جائے گی۔
- تحقیق وترقی کو بڑھاوا دینے کے لئے یونیورسیٹیوں اور کالجوں میں اِن کیوبیشن سینٹر قائم کئے جائیں گے۔
- نانگلوئی سرس پور اور مادی پور میں کل 1800 بستر صلاحیت کے 3 نئے کھولنے کی منصوبہ ہے۔

- سرکار نے شہری حکومتی نظام اور عوامی سیواؤں کا تقسیم سارودھک پاردرشی وسچاروڈھنگ سے کرنے کی عمل شروع کی ہے۔ تاکہ رشوت کو ختم کیا جاسکے۔ اور دہلی کو ملک کا پہلا بدعنوانی سے پاک راجیہ بنایا جاسکے۔
- ایس ڈی ایم آفس سے مختلف طرح کے پامان پتر جاری کرنے میں ہونے والے بدعنوانی کو ختم کرنے کے لئے حکومت نے ای ڈسٹرکٹ سیوائیں شروع کی ہیں۔
- سرکار نے بجلی کے بلوں میں کمی، شہریوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے ہر ایک خاندان کو ہر مہینے 20000 لیٹر کی مفت سپلائی جیسے اہم تدبیر کئے ہیں۔ جس کے لئے 1690 کروڑ روپے کی تعاون کی تجویز ہے۔
- دہلی سرکار نے پیاز اور آلو کا محفوظ ذخیرہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ان اشیاء کی کمی ہونے کی صورت میں انہیں بازار میں لایا جائے گا۔
- 2015-16 میں دہلی کے سبھی کالجوں اور دیہی علاقوں کو مفت وائی فائی خدمت مہیا کرائی جائے گی۔
- لائسنس دینے کا موجودہ طریقہ کی تحقیقی اور تنقیدی عمل کو آسان بنانے کے ترکیب سجھانے کے لئے ایک اعلیٰ افسر سمیتی مقرر کیا گیا ہے۔ یہ سمیتی اپنی سفارشیں 31 جولائی 2015 تک پیش کرے گی۔
- تجارت کرنے میں آسانی اور صحیح فیصلہ لینے کے کارن دہلی جلدی ہی تجارت کے لئے مکمل اختیار والا مقام

دھلی سرکار کے وزیر خزانہ جناب منیش سسودیا نے دھلی اسمبلی میں آپ سرکار کا پھلا بجٹ پیش کیا۔

دہلی سرکار کا بجٹ 2015-16

دہلی سرکار کے وزیر خزانہ جناب منیش سسودیا نے دہلی اسمبلی میں آپ سرکار کا پہلا بجٹ پیش کیا۔

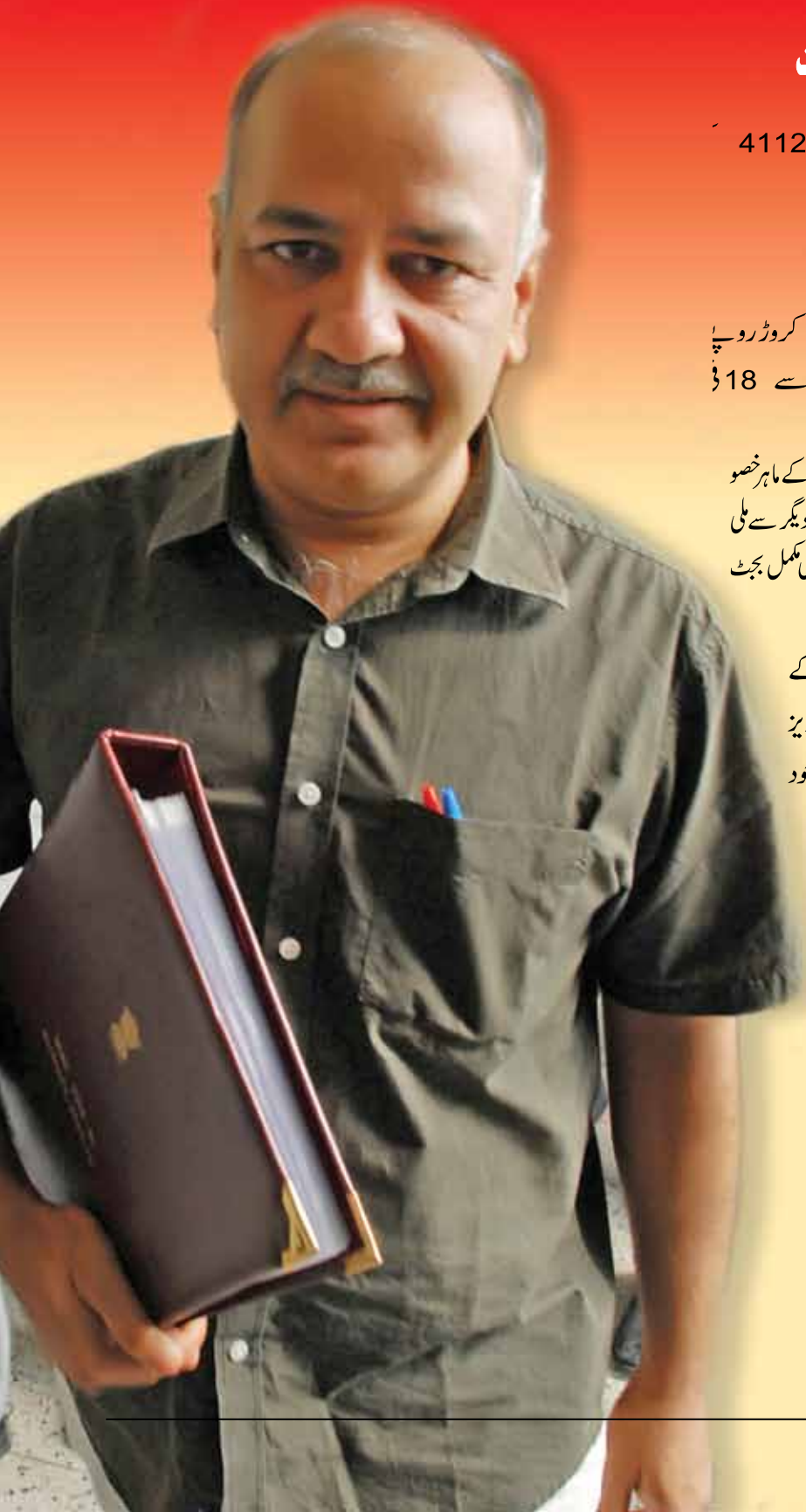

دہلی بجٹ 2015-16 کی خصوصیات

- دہلی سرکار کا سال 2015-16 کے لئے کل تخمینہ 41129 روپے تجویز کیا ہے۔
  - یوجنا بجٹ 19000 کروڑ روپے
  - غیر یوجنا بجٹ 22129 کروڑ روپے
- 2015-16 کے بجٹ کے لئے کل مجوزہ 41129 کروڑ روپے 2014-15 کے مقررہ تخمینہ 34790 کروڑ روپے سے 18 فی زیادہ ہے۔
- یہ ملک کا پہلا سوراج بجٹ ہے جو عوام، تعلیمی اداروں، دیگر علاقوں کے ماہر خصوصی، آر ڈبلو اے شہری سمیتیوں، تجارتی تنظیموں، کارپوریٹ گھرانوں دیگر سے ملی بیش قیمت جانکاری اور سجھاؤ پر منحصر ہے۔ یہ بھارت کا پہلا بھاگیداری مکمل بجٹ ہے۔
- ایک نئی پہل کے روپ میں 253 کروڑ روپے کے بجٹ پراودھان کے ساتھ ''سوراج ندھی'' کی مقرر کر کی تجویز ہے۔ جس کے ذریعہ عوام اپنے علاقے کی ترقی کے لئے ازخود چنے گئے پروگراموں کو لاگو کر سکیں گے۔
- دہلی سرکار نے حکومت کی پرکریا کو فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار دیا ہے۔
- ہر ایک مالیہ ضلع میں دہلی نگرو کاس ایجنسی (ڈی یو ڈی اے) نام کی ایک ایجنسی قائم کرنے کا عزم ہے۔ جس کے ذریعہ عوام سوراج فنڈ اور عزت مآب ایم ایل اے کے ذریعہ ایم ایل اے فنڈ کے تحت مہیا کئے گئے کاموں کو انجام دیا جائے گا۔
- مقامی جماعتوں کو 2015-16 میں مالی مدد کے روپ میں کل 5908 کروڑ روپے تجویز کئے گئے ہیں۔ جو کل بجٹ کا 14.4 فی صد ہے۔

विश्व विरासत

साम्राज्यों की राजधानी दिल्ली

Delhi Tourism

Delhi Heritage Management Secretariat

DELHI GOVERNMENT
Team Delhi, Making things happen

भ्रष्टाचारी ताकतों की तमाम साज़िशों के बावजूद

केजरीवाल सरकार ने रचा इतिहास

भारत के इतिहास में पहली बार

शिक्षा का बजट हुआ डबल (105% बढ़ोत्तरी)

''वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे''

- अब गरीब बच्चों को भी मिलेगी अच्छी शिक्षा।
- सभी सरकारी स्कूलों में आधुनिकतम सुविधायें दी जाएगी।
- 50 सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने का काम शुरू।
- अगले वर्ष सभी सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जायेगा।
- 236 नये स्कूलों पर काम शुरू।
- छात्र–अध्यापक अनुपात सुधारने के लिए 20,000 नये शिक्षकों की भर्ती शुरू।
- शिक्षकों की जवाबदेही के लिए सरकारी स्कूलों की हर कक्षा में CCTV कैमरे।
- शिक्षा के नाम पर माफिया चलाने वाले कुछ प्राइवेट स्कूलों और कालेजों पर कसेगी नकेल।
- उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन– सरकार देगी गारंटी।

''शिक्षा पर व्यय को हम खर्च नहीं बल्कि अपनी भावी पीढ़ी पर निवेश मानते हैं।
अगर हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख गए, तो ये बड़े होकर
अपने परिवार की गरीबी दूर करेंगे और देश का खूब विकास करेंगे''

–अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री, दिल्ली

दिल्ली सरकार
आप की सरकार

श्री सज्जन सिंह यादव, निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054 द्वारा प्रकाशित एवं आकांक्षा इम्प्रेशन्स, 18/36 स्ट्रीट नं. 5, रेलवे लाइन साइड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली–05 द्वारा मुद्रित